वार्षिकी : 2007

01 जनवरी 2007

राज्य शासन ने वर्ष 2006-07 में सीहोर जिले के ग्राम लाड़कुई, विकासखंड नसरुल्लागंज में 50 सीट्स के एक नवीन प्री-मेट्रिक बालक छात्रावास की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की। शासन ने इसकी स्थापना के लिए 5 लाख 26 हजार रुपये राशि लागत की मंजूरी दी।

02 जनवरी 2007

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 275 रुपये करने का फैसला लिया गया। इस फैसले से करीब 11 लाख 43 हजार हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। यह वृद्धि एक अप्रैल 2007 से देय होगी। अभी सरकार 150 रुपये प्रतिमाह की दर पर पेंशन दे रही हैं। केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया। सरकार ने केंद्र सरकार के अंश 200 रुपये को मिलाकर इसे 275 रुपये करने का निर्णय लिया है।

02 जनवरी 2007

मंत्रिपरिषद् ने प्रदेश में चिकित्सकों की कमी को देखते हुए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के एलोपैथी चिकित्सकों की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष तथा एलोपैथी चिकित्सा महाविद्यालयों के शिक्षकों (डेमोस्ट्रेटर्स को छोड़कर) की अधिवार्षिकी आयु 62 वर्ष के स्थान पर 65 वर्ष करने का निर्णय लिया गया।

03 जनवरी 2007

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में स्टोन पार्क स्थापित करने के लिए 585 लाख रुपये लागत की परियोजना का शिलान्यास किया। ग्वालियर और उसके आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध पत्थर सम्पदा का व्यवस्थित रूप से उपयोग करने पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टोन पार्क से स्थानीय गरीब वर्ग को रोजगार तो मुहैया होगा ही, साथ ही पत्थर निर्यात से विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हो सकेगी।

03 जनवरी 2007

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की 50 प्रतिशत राशि मूल वेतन में सम्मिलित करने की घोषणा की। मंहगाई भत्ते की 50 प्रतिशत राशि मूल वेतन में शामिल करने संबंधी आदेश एक अप्रैल 2007 से प्रभावशील होगा। इससे शासकीय कोष में 418 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आयेगा। शासकीय कर्मियों का 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता, मूल वेतन में शामिल करने से पेंशनरों को भी लाभ होगा।

05 जनवरी 2007

नगरों को गंदी बस्तियों के अंबार से बचाने के लिये नियोजित विकास जरूरी है। यह बात लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष तथा देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने इंदौर में कही। श्री आडवाणी ने इंदौर में 27 अरब 45 करोड़ की शहरी नवीनीकरण समन्वित विकास योजना के विमोचन के बाद एक सभा को संबोधित करते हुये कहा कि देश में 40 प्रतिशत आबादी शहरों में रहती है। गांवों में रोजगार की कमी होने से और कृषि पर निवेश नहीं होने से शहरों में

जनसंख्या का दबाव बढ़ा है। पूर्व उपप्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जनता की जरूरतों को समझकर विकास के कार्य किये जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की प्रशंसा करते हुये कहा कि गरीब बेटियों के विवाह की जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश का विकास और जनता का कल्याण राज्य सरकार का एकमात्र लक्ष्य है।

06 जनवरी, 2007

अधिकारी और जनप्रतिनिधि मिलकर कुछ ऐसी कोशिश करें कि किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक बिजली हासिल हो। यह बात पंचायत, ग्रामीण विकास, ग्रामोद्योग एवं जनसंपर्क मंत्री श्री नरेन्द्र तोमर ने उज्जैन में कही। उन्होंने कहा कि किसानों को बिजली तो मिले ही साथ ही बिजली के बिलों का नियमित भुगतान हो ताकि बिजली विभाग भी चल सकें। श्री तोमर ने कहा कि हालांकि मध्यप्रदेश में विद्युत वितरण की स्थिति कुछ सालों में सुधरी है तथा विद्युत उत्पादन के नजरिये से भी मध्यप्रदेश आत्मनिर्भर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त बिजली लोगों तक पहुंचे, इसके लिये आधारभूत संरचना के सुधार के साथ ही तंत्र को भी मजबूत बनाना होगा।

08 जनवरी 2007

आदिवासियों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिये नई स्व-रोजगार योजनायें लागू की जायेंगी। यह बात आदिम जाति कल्याण मंत्री कुंवर विजयशाह ने भोपाल में मध्यप्रदेश वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के दौरान कही। उन्होंने कहा कि आदिवासी तबके के बेरोजगार स्व-रोजगार के जरिये से आगे बढ़ सकें इसके लिये राज्य सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। श्री शाह ने कहा कि स्व-रोजगार की नई योजनायें लाई जायेगी, जिनसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के विकास के लिये जरूरतमंदों को ज्यादा से ज्यादा वित्तीय सहायता मुहैया कराई जायेगी साथ ही ऐसा माहौल बनाया जायेगा, जिससे हितग्राही समय पर ऋणों की अदायगी कर सकें।

10 जनवरी 2007

महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर और मजबूत बनाने के लिये ज्यादा से ज्यादा योजनायें बननी चाहिये। यह बात महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री कुसुम महदेले ने भोपाल में महिला वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय ओरिएंटेशन कार्यशाला को संबोधित करते हुये कही। उन्होंने कहा कि महिला कल्याण की दिशा में जितना काम पिछले तीन सालों में हुआ है उतना दस साल में नहीं हुआ है लेकिन अभी भी महिलाओं के लिये बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि महिला वित्त एवं विकास निगम केंद्र और राज्य शासन की मदद से ऐसी योजनायें बनाये जिनसे महिलायें स्वावलंबी बन सकें। सुश्री कुसुम महदेले ने स्व-सहायता समूहों को भी मजबूत किये जाने की बात कही। स्व-सहायता समूहों को ऋण वगैरह मुहैया कराने में मदद की जानी चाहिये। उन्होंने कहा कि स्व-सहायता समूह भी ऐसे नये कार्यों को हाथ में लें, जो महिलाओं के हित में हों।

11 जनवरी 2007

मध्यप्रदेश सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के राष्ट्रीय खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर सम्मानित करेगा। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने इसके लिये 20 जनवरी 2007 तक आवेदन आमंत्रित किये हैं। मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग को उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के मकसद से वर्ष 2006-2007 से 'खेलखूद एवं सांस्कृतिक/बौद्धिक

प्रतियोगिताओं का आयोजन' योजना शुरू की गई है। इस योजना में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के मध्यप्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जायेगा। इसके लिये नगद राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जायेगी।

13 जनवरी, 2007

मध्यप्रदेश का तेज गति से विकास तथा जन कल्याणकारी योजनाओं पर फौरन अमल सुनिश्चित करने के लिये प्रशासन में जरूरी बदलाव और प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिये भोपाल में दो दिवसीय कार्यशाला 'मंथन 2007' का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शासन तंत्र को चलाने वाले मंत्रिमंडल के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी इस मंथन शिविर में विकास कार्यक्रमों और निर्माण कार्यों में प्रशासनिक विलंब को खत्म करने तथा मानसिकता में बदलाव लाने और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के संबंध में विचार-विमर्श करेंगे।

15 जनवरी 2007

राज्य शासन द्वारा उपभोक्ता संरक्षण गतिविधियों को प्राथमिकता देने के लिये खासतौर पर कोशिश की जा रही है। प्रदेश में उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन को एक सशक्त और व्यापक आधार पर आम उपभोक्ताओं में प्रतिष्ठित करने के लिये शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सक्रिय उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले स्वैच्छिक उपभोक्ता संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य शासन द्वारा राज्य स्तरीय और संभाग स्तरीय पुरस्कार योजना शुरू की गई है। इनमें राज्य स्तर पर तीन पुरस्कार प्रथम 15 हजार रुपये, द्वितीय 10 हजार रुपये, तृतीय 5 हजार रुपये तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जायेंगे। संभाग स्तर पर क्रमशः तीन, दो और एक हजार रुपये तथा प्रशस्ति पत्र दिये जायेंगे। यह पुरस्कार विश्व उपभोक्ता दिवस के मौके पर 15 मार्च, 2007 को प्रदान किया जायेगा। ग्रामीण अंचलों में आदिवासियों और पिछड़े क्षेत्र में कार्यरत संगठनों को प्राथमिकता दी जायेगी।

16 जनवरी 2007

मध्यप्रदेश में कला और साहित्य से जुड़ी प्रतिभाओं को खिलाड़ियों के समान शासकीय नौकरियों में मौके मिलना चाहिये। यह बात संस्कृति राज्यमंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने भोपाल में अखिल भारतीय सिविल सेवा संगीत एवं नृत्य प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में कही। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से मध्यप्रदेश सांस्कृतिक एवं कला के क्षेत्र में समृद्ध रहा है इसे और भी ऊँचाइयां दी हैं भारत भवन ने। श्री शर्मा ने कहा कि शासकीय कर्मियों को अपनी प्रतिभाओं को निखारने के साथ-साथ राज्य को देश में मुकाम दिलाने के लिये लगातार कोशिश करना चाहिये।

17 जनवरी 2007

विज्ञान का इस्तेमाल कृषि के नवीनीकरण और इसके नये विकल्पों को तलाश करने में किये जाने की जरूरत है। यह बात राज्यपाल डॉ. बलराम जाखड़ ने भोपाल में विज्ञान प्रसार के 'विशेष प्रयोग विषय' पर आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन मौके पर कही। उन्होंने विज्ञान के फायदे गांव तक पहुंचाने पर जोर देते हुये कहा कि वहां का जीवन मुश्किल और परेशानियों से भरा है। राज्यपाल ने कहा कि आज भी गांवों की 65 प्रतिशत खेती मानसून पर टिकी है। सिर्फ 35 प्रतिशत जमीन ही सिंचित है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को गांव तक ले जाने पर वैज्ञानिकों को आव्हान करते हुये कहा कि वे गांव में जाकर किसान की मदद करें।

19 जनवरी 2007

मध्यप्रदेश में इस साल हरियाली महोत्सव में दस करोड़ पौधों का रोपण किया जायेगा, जिसमें से चार करोड़ बांस के पौधे होंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना की सफलता के लिये वनमंत्री श्री हिम्मत कोठारी के निर्देश पर वन संरक्षकों द्वारा वर्ष 2007 के हरियाली महोत्सव के लिये तीन करोड़ 64 लाख बांस के राईजोम और 72 लाख पौधे तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है। मध्यप्रदेश बांस के वनों के लिये मशहूर है यह और बात है कि पिछले कई दशकों में यह महसूस किया गया है कि बांस के वन कम होते जा रहे हैं। हालांकि बांस एक बहुपयोगी प्रजाति है। यह ग्रामीण परिवेश के लिये बहुत ही उपयोगी वनोपज है।

20 जनवरी, 2007

मध्यप्रदेश में दृष्टिहीनता की दर में कमी लाने के उद्देश्य से शासन द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है। मध्यप्रदेश ने दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम में लगातार दूसरे साल 110 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की है। इस साल एक लाख नौ हजार 929 के लक्ष्य के विरुद्ध एक लाख 21 हजार 307 मोतियाबिंद के ऑपरेशन कर महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की गई है। यह लक्ष्य का 110 प्रतिशत है। गौरतलब है कि आने वाले सालों में नेत्र चिकित्सा सुविधायें दूरदराज स्थानों तथा आम लोगों तक पहुंचाने के लिये प्रत्येक पचास हजार जनसंख्या में एक 'विजन सेंटर' स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस साल 80 विजन सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही लोगों को नेत्रदान करने के लिये जागृत भी करना है।

21 जनवरी, 2007

पचास सालों के विकास की कसर मय ब्याज के दो सालों में पूरी कर दी जायेगी। यह बात मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सरई गांव में आदिवासी सम्मेलन को संबोधित करते हुये कही। उन्होंने कहा कि विकास और जनकल्याण के कार्यों में पैसे की कमी नहीं आने दी जायेगी। श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के कारगर फैसले किये गये, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर बन सके। उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं की शिष्यावृत्ति में भी बढ़ोत्तरी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातियों को वन भूमि में पुराने कब्जे के पट्टे दिये जायेंगे। उन्हें बेदखल नहीं किया जायेगा। साथ ही वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया जायेगा, ताकि उनमें भी भरपूर विकास कार्य हो सके। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगारोन्मुखी और तकनीकी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

22 जनवरी 2007

अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा सेवा मुहैया कराने के साथ-साथ नर्सों और पैरामेडिकल स्टॉफ की संख्या बढ़ाने के लिये खास कोशिश की जा रही है। यह बात लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अजय विश्नोई ने भोपाल में रेडक्रास सोसायटी में फिजियोथेरेपी सेंटर और निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर के समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहां कि राज्य सरकार ने अपने खर्च पर पांच सौ नर्सों को प्रशिक्षण के लिये चुना है। श्री विश्नोई ने कहा कि नर्सिंग प्रशिक्षण के बाद यह सभी नर्सें सरकारी अस्पतालों में अपनी सेवायें दे सकेंगी। उन्होंने कहा कि इसी तरह लगभग 800 लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर को भी शासन अपने खर्च पर प्रशिक्षित कर रहा है।

24 जनवरी 2007

मध्यप्रदेश में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने तथा मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिये परिवहन और उपचार योजना के तहत अब तक दो लाख 64 हजार 656 गर्भवती महिलायें फायदा उठा चुकी हैं। 25 सितंबर 2004 से लागू इस योजना के प्रारंभिक वर्ष 2004-05 में 16 हजार 917 गर्भवती महिलाओं को प्रसव सुविधा का फायदा मिला था। गौरतलब है कि प्रदेश में दो साल से चल रही इस महत्वपूर्ण योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजारने वाले परिवार की महिलाओं को शासकीय अस्पताल में प्रसव कराने पर आर्थिक सहायता मिल रही है।

26 जनवरी 2007

मध्यप्रदेश शासन ने गणतंत्र दिवस की सौगात के तौर पर नवगठित जिलों बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर को नये जिला परिवहन कार्यालय खोलने की मंजूरी दी है। यह मंजूरी परिवहन मंत्री श्री हिम्मत कोठारी ने भोपाल में दी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही आवश्यक अमले के लिये नये पद भी स्वीकृत किये गये हैं। श्री कोठारी ने कहा कि इन जिलों में प्रत्येक जिला परिवहन कार्यालय के लिये 13 पदों के अनुसार कुल 39 नये पद स्वीकृत हुये हैं। परिवहन मंत्री ने कहा कि नवगठित जिलों में खुलने वाले कार्यालयों का आरंभ से ही कम्प्यूटरीकरण किया जायेगा। एकल खिड़की प्रणाली भी कायम की जायेगी ताकि आम परिवहन संबंधी मामलों को फौरन निपटाया जाये।

27 जनवरी, 2007

मध्यप्रदेश में अगले पांच सालों में स्त्री-पुरुष समानता के लक्ष्य को हासिल करने के लिये अनेक अभिनव योजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा। यह बात मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में महिला एवं बाल विकास संचालनालय के भवन की आधारशिला रखने के दौरान कही। उन्होंने कहा कि बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने के साथ ही कक्षा नवमी से अन्य ग्राम में अध्ययन के लिये जाने पर निःशुल्क साइकिल का वितरण और गांव की बेटी योजना का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्दी ही ऐसी भी योजना शुरू होगी जिसमें बेटी के जन्म के साथ डाकघर में राशि जमा कराई जायेगी जो उसके 25 बरस की होने पर एक लाख रुपये के रूप में उसे मिलेगी।

28 जनवरी, 2007

मध्यप्रदेश में नर्मदा घाटी विकास परियोजनाओं के निर्माण से प्रभावित परिवारों की पुनर्वास संबंधी शिकायतों का स्वतंत्र रूप से निराकरण करने के लिये गठित दो पृथक शिकायत निवारण प्राधिकरणों ने दिसंबर तक 19 हजार 629 शिकायतों का निराकरण कर दिया है। गौरतलब है कि गुजरात में निर्माणाधीन सरदार सरोवर परियोजना प्रभावितों की शिकायतों के निराकरण के लिये उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जी.जी. सोहनी की अध्यक्षता में गठित शिकायत निवारण प्राधिकरण कार्यरत हैं।

29 जनवरी 2007

अनुसूचित जाति की गरीब, विधवा महिलाओं और अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराना हमारी प्राथमिकता है। यह बात अनुसूचित जाति कल्याण तथा वन राज्यमंत्री श्री प्रकाश सोनकर ने इंदौर में कही। उन्होंने कहा कि गरीब

महिलाओं को स्व-रोजगार स्थापना में मदद के लिये अनुसूचित जाति बहुल बस्तियों में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किये जायेंगे, साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के बाद उन्हें रोजगार के लिये आर्थिक मदद भी दी जायेगी। श्री सोनकर ने कहा कि राज्य शासन ने अनुसूचित जाति कल्याण के लिये अनेक योजनायें शुरू की हैं, उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे जागरूक बनें और इन योजनाओं का फायदा उठायें।

30 जनवरी 2007

मध्यप्रदेश शासन ने शासकीय सेवकों को अपनी निजी जरूरतों की पूर्ति के लिये ऋण की सुविधा मुहैया कराने के लिये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक करारनामे पर हस्ताक्षर किये हैं। यह बात संचालक संस्थागत वित्त श्री अशोक बर्णवाल ने भोपाल में कही। उन्होंने बताया कि शासकीय सेवकों को गृह निर्माण अग्रिम, कार अग्रिम, दुपहिया वाहन अग्रिम और उपभोक्ता सामग्री खरीदने के लिये राज्य शासन ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ऋण मुहैया कराने का फैसला लिया है। श्री बर्णवाल ने कहा कि अब शासकीय सेवकों को रियायती ब्याज दरों पर सेंट्रल बैंक से तयशुदा शर्तों के अधीन विभिन्न ऋणों की सुविधा मुहैया कराई जायेगी। बैंक द्वारा किसी भी ऋण की स्वीकृति की प्रक्रिया की कोई फीस नहीं ली जायेगी।

31 जनवरी 2007

दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के तहत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन गुजारने वाले परिवारों के लिये जिलों को पचास लाख अंत्योदय उपचार कार्ड जारी किये जा चुके हैं। मध्यप्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के तहत पूर्व में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन गुजारने वाले हितग्राहियों को अंत्योदय उपचार कार्ड जारी किये गये थे। राज्य सरकार ने बाद में इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को भी लाभान्वित किये जाने के लिये योजना का विस्तार किया गया है। पूर्व में जारी लगभग 21 लाख अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों के परिवारों के अंत्योदय उपचार कार्ड निरस्त कर नये कार्ड जारी किये जाने हैं। वहीं तकरीबन 29 लाख अंत्योदय उपचार कार्ड गैर अनुसूचित जाति, जनजाति के गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे पात्र हितग्राहियों के बनाये जायेंगे।

01 फरवरी 2007

मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की गतिविधियों की भोपाल में एक बैठक में समीक्षा की गई। बैठक में समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार को स्व-प्रेरणा से कार्यवाही करने, आदिवासी वर्गों की भूमि को कब्जे से मुक्त कराने तथा राज्य शासन द्वारा प्राथमिकता के आधार पर आदिवासी पंचायत में की गई घोषणायें प्रमुख उपलब्धियां रहीं। आयोग के सदस्यों के लिये एक कक्ष अतिरिक्त रूप से भोपाल स्थित राजीव गांधी भवन में नागरिक अधिकार संरक्षण संचालनालय से उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की गई। आयोग के सचिव का पद अपर संचालक स्तर का बनाया जाने के अलावा पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक आयोग के विभागीय सेटअप के मुताबिक नये पद सृजित करने पर सहमति भी व्यक्त की गई।

02 फरवरी 2007

एन.सी.सी. हमारे विद्यार्थियों में देश भक्ति का जज्बा पैदा करने और राष्ट्र के निर्माण के लिये संकल्पित होकर कार्य करने की प्रेरणा देने वाला महत्वपूर्ण संगठन है। यह बात मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी. कैडेट्स द्वारा प्रस्तुत नाटक के मंचन और पुरस्कार वितरण समारोह में कही। उन्होंने कहा कि

राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निभाकर युवा अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश विकसित राज्य बनने की तैयारी कर रहा है। सभी के संकल्प और सहयोग से मध्यप्रदेश जल्दी ही विकसित राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों के साथ श्रेष्ठ मानव संसाधन भी हैं।

03 फरवरी 2007

मध्यप्रदेश के बच्चों में कुपोषण से बचाव और उसके निदान के लिये बाल संजीवनी अभियान 2001 से चलाया जा रहा है। इस अभियान ने अब तक 9 चरण पूरे कर लिये हैं। वर्ष 2001 में पहले चरण के दौरान कुपोषण का प्रतिशत 57.57 था जो 9वें बाल संजीवनी अभियान के बाद घटकर 47.36 प्रतिशत रह गया है। इसी तरह 9वें बाल संजीवनी अभियान के बाद गंभीर कुपोषण का प्रतिशत 5.50 से घटकर 0.78 प्रतिशत रह गया है। यह राज्य सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। गौरतलब है कि राज्य में छोटे बच्चों में कुपोषण को रोकने के लिये नियमित रूप से साल में दो बार बाल संजीवनी अभियान चलाया जा रहा है।

04 फरवरी 2007

मध्यप्रदेश में नर्मदा घाटी जलाशय मछली उत्पादन के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। घाटी में बन रहे नये सात जलाशयों से हर साल साढ़े तीन हजार मेट्रिक टन से ज्यादा मछली का उत्पादन होगा। इस उत्पादन का मूल्य 25 करोड़ 77 लाख रुपये आंका गया है। गौरतलब है कि खंडवा जिले में इंदिरा सागर बांध से 913 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का देश का सबसे बड़ा जलाशय निर्मित हुआ है। इस जलाशय में 59 हजार हेक्टेयर जल क्षेत्र मछली उत्पादन के लिये सुलभ है।

07 फरवरी 2007

जल संसाधन विभाग ने सीहोर राजगढ़ और भोपाल जिले की सात सिंचाई योजनाओं के लिये 13 करोड़ 17 लाख रुपये की प्रशासकीय मंजूरी प्रदान की है। भोपाल से मिली खबरों के मुताबिक स्वीकृत सिंचाई योजनाओं में सीहोर जिले की पांच तथा राजगढ़ और भोपाल की एक-एक सिंचाई योजना शामिल है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल डॉ. बलराम जाखड़ ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के परामर्श पर पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामोद्योग तथा जनसंपर्क मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं सामाजिक न्याय मंत्री श्री रामपाल सिंह का त्याग पत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है।

08 फरवरी 2007

चुनाव आयोग द्वारा प्रदेश के दो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों ग्वालियर और सीधी तथा एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र उदयपुरा के खाली जगह को भरने के लिये उपचुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित किया गया है। इन संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित जिलों ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, सीधी और रायसेन में 6 फरवरी से निर्वाचन संपन्न होने तक की अवधि के लिये आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। यह आदर्श आचार संहिता राज्य शासन, राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों के लिये लागू होगी। उप चुनाव में आगामी 8 मार्च को होने वाले मतदान के लिये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जायेगा।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में मौजूद विभागों के साथ-साथ जनसंपर्क विभाग की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। आदेश के मुताबिक गृह तथा नर्मदा घाटी विकास राज्यमंत्री श्री नागेन्द्र सिंह को जनसंपर्क विभाग, आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री विजय शाह को ग्रामोद्योग विभाग, महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री कुसुम सिंह महदेले को सामाजिक न्याय विभाग, श्रम तथा अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री जगदीश देवड़ा को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण और जैव विविधता तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रुस्तम सिंह को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और सामान्य प्रशासन का दायित्व सौंपा गया है।

10 फरवरी 2007

मध्यप्रदेश शासन ने प्रदेश के शक्कर कारखानों को पूरी क्षमता से पिराई का काम करने के लिये आगाह किया है। इस निर्णय के तहत गन्ना पिराई की हर हफ्ते समीक्षा की जायेगी। कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भोपाल में शक्कर कारखाना प्रतिनिधियों के साथ बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि कारखाने अपनी पूरी क्षमता से गन्ना पिराई का काम नहीं कर रहे हैं। कारखाना प्रतिनिधियों ने शासन को आश्वत किया है कि आरक्षित क्षेत्र के गन्ने की संपूर्ण मात्रा का इस्तेमाल करेंगे और किसानों को इसका समय और उचित मूल्य देंगे। गौरतलब है कि इस साल मध्यप्रदेश में लगभग 76000 हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ना की बोनी हुई है। इस गन्ने का इस्तेमाल प्रदेश के निजी और सहकारी क्षेत्र में स्थित शक्कर कारखानों खाण्डसारी मिलों तथा गुड़ बनाने में किया जाता है।

11 फरवरी 2007

मध्यप्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं में पर्यावरण तथा परिस्थितिकीय विकास के लिये 'विद्या वन' के रूप में अभिनव योजना शुरू की जा रही है। यह बात वनमंत्री श्री हिम्मत कोठारी ने भोपाल में कही। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश की दो सौ शैक्षणिक संस्थाओं में हर साल दो लाख पौधे लगाये जायेंगे। श्री कोठारी ने कहा कि इस प्रकार 11वीं पंचवर्षीय योजना में एक हजार शैक्षणिक संस्थाओं में पाँच सालों के दौरान दस लाख पौधे और लगाये जायेंगे। वनमंत्री ने कहा कि विद्या वन योजना के माध्यम से विद्यार्थियों और स्थानीय समुदाय को वन संवर्द्धन के प्रति जागरुक किया जा सकेगा। प्रदेश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों की शैक्षणिक संस्थाओं में यह रोपण किया जायेगा। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

12 फरवरी 2007

मध्यप्रदेश शासन ने मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं से जुड़े सभी कर्मचारियों की सेवायें जरूरी घोषित कर दी हैं। यह घोषणा मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण और विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 के तहत की गई है। आदेश के तहत नियुक्त कर्मचारी और अधिकारी परीक्षाओं के संचालन को लेकर सभी जरूरी कार्यों के लिये दिये गये कामों से इंकार नहीं कर सकेंगे। गौरतलब है कि यह प्रतिबंध 15 फरवरी 2007 से तीन महीने के लिये लागू रहेगा।

13 फरवरी 2007

नशामुक्ति अभियान के तहत संचालित की जा रही गतिविधियों में ब्राउन शुगर स्मैक को भी शामिल किया जाये। यह बात महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री कुसुम महदेले ने भोपाल में एक बैठक में कही। उन्होंने कहा कि ऐसे खतरनाक नशे के आदि हो चुके लोगों का इलाज कर उन्हें नशामुक्त किया जाये। सुश्री महदेले ने कहा कि शासन अभी जिन 192 स्वैच्छिक संस्थाओं को तम्बाकू, धूम्रपान मद्यनिषेध जैसी नशाबंदी गतिविधियों के संचालन के लिये अनुदान देता है, वे

अपनी गतिविधियों में ब्राउन शुगर और स्मैक को भी शामिल करें वरना भविष्य में शासन उन्हें अनुदान नहीं देगा। उन्होंने नये सिरे से विकलांगों का सर्वे कराने के लिये कहा तथा उनके कल्याण के लिये ईमानदारी और स्वप्रेरणा से कोशिश करने को कहा।

14 फरवरी 2007

मध्यप्रदेश में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत अब तक भोपाल, जबलपुर और इंदौर शहरों के विकास के लिये कुल 1492 करोड़ रुपये लागत की परियोजनाओं को मंजूरी हासिल हो चुकी है। भोपाल से प्राप्त खबरों के मुताबिक विभिन्न 31 परियोजनाओं के तहत इन शहरों में पेयजल प्रदाय, सीवरेज सिस्टम, शहरी यातायात प्रबंधन और शहरी गरीबों के लिये आवास तथा शहरी अधोसंरचना विकास के कार्यों को मूर्तरूप दिया जा रहा है। इन तीनों शहरों में शहरी गरीबों के लिये 32 हजार 313 सुविधायुक्त आवासों के निर्माण की कुल 504 करोड़ रुपये लागत की परियोजनायें भी शामिल हैं।

अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंडित श्यामाचरण शुक्ल का रायपुर में निधन हो गया। रायपुर से मिली खबरों के मुताबिक 82 वर्षीय श्री शुक्ल लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। उनका अंतिम संस्कार रायपुर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया।

16 फरवरी 2007

दृढ़ इच्छाशक्ति से बढ़कर दुनिया में कोई भी चीज मजबूत नहीं होती है। यह बात विधानसभा अध्यक्ष श्री ईश्वरदास रोहाणी ने सतना में कही। उन्होंने कहा कि बालिकायें संकल्प ले और शिक्षा के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़े। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक वितरण समारोह को संबोधित करते हुये श्री रोहाणी ने बालिकाओं को संबोधित करते हुये कहा कि इक्कीसवीं सदी प्रतिस्पर्धा की सही है, जिसमें मेहनत करने वाले व्यक्ति को ही कामयाबी मिलेगी और वही अपने जीवन में सुखी रह सकता है। उन्होंने कहा कि बालिकायें संकल्प लेकर अपने लक्ष्य को पूरा कर देश का नाम गौरवान्वित करें।

17 फरवरी 2007

तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त की कमी बहुत कमी है। ऐसे वक्त में किसी निर्धारित काउंटर में जाकर बिजली बिल जमा करना बेहद मुश्किल है इसी बात को मद्देनजर रखते हुये पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने लोगों की इस असुविधा के निवारण के लिये सुलभ बिजली बिल भुगतान सेवा शुरू कर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान की है। यह बात मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री ईश्वरदास रोहाणी ने जबलपुर में बिजली दफ्तर में एनीवेयर पेमेंट सुविधा का शुभारंभ के दौरान कही।

18 फरवरी 2007

मध्यप्रदेश शासन द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री पवन श्रीवास्तव को संचालक संस्कृति पदस्थ किया गया है। श्री पवन श्रीवास्तव वर्ष 1992 के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। श्री श्रीवास्तव वर्तमान में उप पुलिस महानिरीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग में पदस्थ हैं। वे श्री पंकज राग का स्थान लेंगे।

19 फरवरी 2007

अब हर उप स्वास्थ्य केंद्र पर लेबर रूम (प्रसूति कक्ष) बनाया जायेगा। यह बात लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अजय विश्नोई ने गुना में कही। उन्होंने कहा कि सिर्फ गुना जिले में ही पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाये जायेंगे। श्री विश्नोई ने कहा कि सरकार उप स्वास्थ्य केंद्रों और मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि ए.एन.एम. के 200 पद सृजित करके भर्ती की गई है, जिन्हें पांच साल के लिये सरकारी खर्च पर प्रशिक्षित कराया जा रहा है। श्री अजय विश्नोई ने कहा कि उल्लेखनीय कार्य करने वाले चिकित्सकों को राज्य स्तर पर पुरस्कार देने की व्यवस्था की गई है।

21 फरवरी 2007

वाणिज्यिक कर की बकाया वसूली के लिये योजनाबद्ध तरीके से कोशिश की जाये। यह बात वाणिज्यिक कर आयुक्त श्री पी.के. दास ने भोपाल में विभागीय अधिकारियों को संबोधित करते हुये कही। उन्होंने कहा कि पांच लाख रुपये से ज्यादा की बकाया वसूली के प्रकरणों में व्यवसाय चालू हो तो स्टॉक इन्वेन्ट्री जप्त कर और बैंक खाते बंद करके वसूली सुनिश्चित की जायेगी। श्री दास ने कहा कि बड़े बकायेदारों के पंजीयन निरस्त किये जायेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में वाणिज्यिक कर की बकाया वसूली के लिये चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत पिछले तीन महीने में 206 करोड़ तीन लाख रुपये की वसूली की गयी है। एक नवंबर से शुरू किये गये इस अभियान के तहत मार्च के अंत तक करीब पांच सौ करोड़ रुपये की वसूली की जाना है।

22 फरवरी 2007

मध्यप्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों के लिये नगरीय निकायों से अलग करने के बारे में आयुक्त नगरीय प्रशासन और आयुक्त उद्योग चर्चा का प्रस्ताव तैयार करेंगे। उसके बाद नगरीय निकाय कानून में आवश्यक संशोधन करने की कार्यवाही की जायेगी। यह बात उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने भोपाल में एक बैठक में कही। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में खजुराहो में संपन्न निवेशकों की बैठक में घोषणा की थी कि औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधायें मुहैया करने के लिये नगरीय निकायों से पृथक एक अलग निकाय गठित किया जायेगा। ऐसी ही घोषणा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने भी की है।

23 फरवरी 2007

मध्यप्रदेश में गेहूं और चना के समर्थन मूल्य पर समय पर खरीदी सुनिश्चित की जायेगी। समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिये धनराशि की पूरी व्यवस्था रखी जायेगी, जिससे किसानों को उनकी उपज का फौरन भुगतान किया जा सके। यह बात मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में एक बैठक में कही। उन्होंने कहा कि खरीदी के लिये पर्याप्त खरीदी केंद्र बनाये जायें, साथ ही अनाज के संग्रहण के लिये बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाये। मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं की आवक बढ़ने के साथ ही गेहूं के भाव कम होने की स्थिति में समर्थन मूल्य पर फौरन खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

24 फरवरी 2007

राज्य शासन द्वारा संचालित गरीब एवं कुपोषित बच्चों के संस्थागत उपचार एवं पोषण पुनर्वास हेतु संचालित बाल शक्ति परियोजना का क्रियान्वयन आर.सी.एच.-क्ष्क्ष् (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम) द्वारा किया जायेगा। पूर्व में यह योजना डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेव्हलपमेंट यू.के. (डी.एफ.आई.डी.) की आर्थिक मदद से चलाई जा रही थी जिसकी अवधि गत 31 दिसंबर को खत्म हो चुकी है। योजना का क्रियान्वयन जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य समितियों द्वारा किया जाता है अब तक 102 पोषण पुनर्वास केंद्र स्थापित किये जा चुके हैं, जिनके माध्यम से 7182 बच्चों का उपचार एवं उनकी माताओं को पोषण पुनर्वास प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। बाल शक्ति योजना का क्रियान्वयन स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आपसी समन्वय के साथ किया जा रहा है। योजना का पहला चरण खंड स्तर पर जांच शिविरों का आयोजन है जिसमें शिशुरोग विशेषज्ञ द्वारा कुपोषित बच्चों की जांच कर चिकित्सालय में भर्ती हेतु रिफर किया जाता है। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य कुपोषण की गंभीरता के आधार पर उन्हें संस्थागत उपचार उपलब्ध कराना है।

25 फरवरी 2007

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि निर्धन वर्ग की कन्याओं के विवाह के लिए किया गया सहयोग किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। अभावग्रस्त व्यक्तियों की सहायता करने वालों को प्राप्त पुण्य सबसे महत्वपूर्ण पुण्य है। मध्यप्रदेश सरकार की कन्यादान योजना का भी यही लक्ष्य है। मुख्यमंत्री भोपाल में लालघाटी स्थित गुफा मंदिर परिसर में श्री भगवत सेवा जन समिति की ओर से आयोजित 42 निर्धन कन्याओं के विवाह समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने समारोह में कहा कि गरीब कन्याओं के विवाह के लिए पहल करने वाली संस्थाएं अनुकरणीय काम कर रही हैं। ऐसी संस्थाओं को सरकार पूरा प्रोत्साहन देगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लक्ष्मी लाड़ली योजना की विस्तृत जानकारी दी।

26 फरवरी 2007

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने औद्योगिक विकास केंद्रों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे किसी भी हालत में औद्योगिक विकास केंद्रों की भूमि पर अतिक्रमण न होने दें। श्री गौर ने उक्त निर्देश वाणिज्य, उद्योग और रोजगार तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक में दिये। इस बैठक में प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति, जनजाति स्वरोजगार योजना, लघु उद्योगों की स्थापना, अनुदान, अधोसंरचना विकास, औद्योगिक विकास केंद्रों, आटो टेस्टिंग ट्रेक, एस.ई.जेड., पंजीयक रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्था, एस.आई.डी.सी., लघु उद्योग निगम, ट्राइफेक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम, एम.पी. एग्रो बोर्ड की प्रगति की जानकारी दी गई। बैठक में समिति के सदस्य विधायक श्री ओमप्रकाश सकलेचा एवं बुरहानपुर के विधायक श्री हमीद काजी मौजूद थे।

27 फरवरी 2007

जल संसाधन विभाग द्वारा राज्य की चार उद्वहन सिंचाई योजना की कुल 952 लाख से ज्यादा की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। प्रदेश के मंदसौर और सीहोर जिले की इन योजनाओं से 1545 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। जिन उद्वहन सिंचाई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है उनमें मंदसौर जिले

की रामनगर उद्वहन सिंचाई योजना की प्रशासकीय स्वीकृति 140.20 लाख रुपये जारी की गई है। इससे 181.37 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई किया जाना प्रस्तावित है।

28 फरवरी 2007

तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण परियोजना के संचालन के लिये राज्य शासन द्वारा सशक्त समिति का गठन किया गया है। इस परियोजना का संचालन मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम के द्वारा संचालित किया जायेगा। इस समिति के मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे। सदस्यों के रूप में प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास, प्रमुख सचिव राजस्व, प्रमुख सचिव कृषि, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास, प्रमुख सचिव समाज कल्याण सम्मिलित रहेंगे। प्रबंध संचालक महिला एवं वित्त एवं विकास निगम को समिति का सदस्य सचिव मनोनीत किया गया है। यह समिति तेजस्विनी परियोजना के ढांचे के गठन और संचालन के संबंध में दिशा-निर्देश तथा स्वीकृति देगी तथा हर छह महीने में बैठक तथा कार्यक्रम की समीक्षा की जायेगी।

03 मार्च 2007

मध्यप्रदेश शासन ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा-निर्देशों में किये गये प्रावधान के अनुक्रम में एक समिति का गठन किया है। सूत्रों के मुताबिक इस समिति का अध्यक्ष विकास आयुक्त/अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग को बनाया गया है। शासन ने सदस्य के रूप में प्रमुख सचिव/सचिव लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा प्रमुख सचिव/सचिव योजना तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को शामिल किया है। यह समिति वर्ष में एक बार जिला प्राधिकारियों और संसद सदस्यों के साथ सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास के तहत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा करेगी।

05 मार्च 2007

मध्यप्रदेश में इस महीने से विद्युत उत्पादन क्षमता में 500 मेगावाट का इजाफा हो जायेगा। यह होगा संजय गांधी ताप विद्युत गृह की बिरसिंहपुर इकाई से जहां 31 मार्च 2007 तक उत्पादन शुरू हो जायेगा। यह बात ऊर्जा मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने भोपाल में इस परियोजना का समय पर पूरा करने के निर्देश देते हुये कही। उन्होंने कहा कि इसे मिलाकर पिछले तीन सालों में विद्युत उत्पादन क्षमता में कुल 3298.7 मेगावाट का इजाफा हो जायेगा। अभी तक तीन सालों में 1898.7 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ी है।

06 मार्च 2007

मध्यप्रदेश में सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने के लिये आगामी वित्तीय वर्ष में 81 लघु और लघुतम सिंचाई योजनाओं पर काम शुरू होगा। इन 81 योजनाओं में 6 लघु और लघुतम सिंचाई योजनाओं का निर्माण कार्य शुरू होगा जबकि 75 नयी योजनाओं के सर्वेक्षण और रूपांकन कार्य की शुरूआत होगी। आगामी वित्तीय वर्ष में इन सभी कार्यों के लिये जल संसाधन विभाग के आयोजना बजट में वित्तीय प्रावधान किया गया है। प्रदेश में सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने के लिये 15 जिलों में 75 नवीन लघु और लघुत्तम सिंचाई योजनाओं के सर्वेक्षण तथा रूपांकन कार्य के लिये भी जल संसाधन विभाग के आयोजना बजट में वित्तीय प्रावधान किया गया है।

10 मार्च 2007

शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिये। यह बात मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्योपुर जिले के ग्राम दातरदा में ग्रामीणों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि जनदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों से सीधी बात कर योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से जो शिकायतें, समस्यायें और सुझाव आयेंगे उनकी समीक्षा कर योजनाओं को और कारगर बनाया जायेगा। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने का आव्हान भी आमजन से किया।

12 मार्च 2007

श्री पी.पी. तिवारी मध्यप्रदेश के नये मुख्य सूचना आयुक्त होंगे। प्रमुख सचिव विधि श्री तिवारी की अनुशंसा चयन समिति ने की है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुनादेवी और ग्रामीण विकास मंत्री श्री रुस्तमसिंह की चयन समिति की बैठक भोपाल में हुई जिसमें प्रमुख सचिव विधि श्री पी.पी. तिवारी को मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिये अनुशंसा की है।

13 मार्च 2007

मध्यप्रदेश में 44 जिलों में पांच दुग्ध संघों के माध्यम से त्रिस्तरीय संरचना का संचालन किया जा रहा है। डेयरी व्यवसाय में महिलाओं की भागीदारी में इजाफा करने के मकसद से भारत सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दुग्ध संघों के दुग्धांचल में 98 दुग्ध सहकारी समितियों के गठन के लिये तीन वर्षीय महिला डेयरी परियोजना को स्वीकृति दी गई है। परियोजना का क्रियान्वयन दुग्ध संघों द्वारा सीहोर, देवास, शाजापुर, मुरैना और सिवनी जिलों में पिछले छह सालों से किया गया है। परियोजना के तहत जनवरी 07 तक 98 महिला सहकारी दुग्ध समितियों का गठन करते हुये चार हजार 800 महिला सदस्यों को सहकारी डेयरी आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित किया गया है। इस योजना के तहत महिला सदस्यों को दुग्ध व्यवसाय शुरू किये जाने के लिये उन्नत नस्ल के दुधारु पशु स्ववित्त एवं स्वर्ण जयंती स्व-रोजगार ग्राम योजना के तहत मुहैया कराये जायेंगे।

14 मार्च 2007

मध्यप्रदेश में दुधारू पशुओं से ज्यादा से ज्यादा दूध हासिल करने के तहत उन्हें आक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाये जाने पर रोक लगाई गई है। यह बात आयुक्त पशु चिकित्सा सेवाएं श्रीमती शिखा दुबे ने सभी जिला कलेक्टरों को भेजे एक पत्र में कही। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि आक्सीटोसिन इंजेक्शन के ज्यादा और अनावश्यक इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिये हैं। शिड्यूल 'एच' के तहत इस इंजेक्शन की बिक्री या इस्तेमाल पर सिर्फ पंजीकृत पशु चिकित्सा स्नातकों के प्रिस्क्रिप्शन पर ही किया जाये। अन्य व्यक्ति इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली ने एक परिपत्र जारी कर आक्सीटोसिन इंजेक्शन को शिड्यूल 'एच' में शामिल कर ज्यादा दूध के लालच में दुधारू पशुओं को यह इंजेक्शन लगाने संबंधी दुरुपयोग कर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।

16 मार्च 2007

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में खेल गतिविधियों के विस्तार और खिलाड़ियों को दी जा रही सुविधाओं को देखते हुये मध्यप्रदेश के खिलाड़ी ओलम्पिक खेलों में अवश्य पदक जीतकर लायेंगे। श्री चौहान ने कहा कि ओलम्पिक खेलों में पदक लाने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार की अधिक राशि दी जायेगी। प्रदेश के खिलाड़ियों को

खेल किट और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं। इसके अच्छे परिणाम आये हैं और राष्ट्रीय खेलों में मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने कई पदक जीते हैं। श्री चौहान ने यह बात भोपाल स्थित रवीन्द्र भवन में 33वें राष्ट्रीय खेल गुवाहाटी, 12वें राष्ट्रीय खेल युवा उत्सव, पुणे और राज्य स्तरीय युवा अभियान-2007 के पदक विजेता खिलाड़ी प्रतिभाओं को सम्मानित करते हुए कही।

17 मार्च 2007

मध्यप्रदेश शासन ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के जरिये वित्त पोषित तथा यूनिसेफ द्वारा सहायता प्राप्त शालेय किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम को उसके वर्तमान स्वरूप में मध्यप्रदेश में संचालित नहीं करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री अर्जुन सिंह को राज्य शासन के इस फैसले से अवगत कराया है। मुख्यमंत्री ने भेजे गये एक पत्र में कहा है कि मेरा यह मत है कि हमें अपनी भावी पीढ़ी को योग शिक्षा और भारतीय संस्कृति तथा मूल्यों की शिक्षा देना चाहिये इसलिये शासन ने यह फैसला लिया है कि वर्तमान स्वरूप में शालेय किशोरावस्था कार्यक्रम मध्यप्रदेश में संचालित नहीं किया जाये।

18 मार्च 2007

मध्यप्रदेश शासन ने शक्कर कारखानों के क्षेत्र से दूसरे शक्कर कारखानों को किसानों द्वारा गन्ना भेजने की स्थिति में पच्चीस रुपये प्रति क्विंटल परिवहन अनुदान देने का फैसला लिया गया है। राज्य शासन ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों और उपसंचालक कृषि को गन्ना परिवहन पर अनुदान देने के लिये मार्गदर्शी निर्देश भेज दिये हैं। इस साल गन्ने की अच्छी पैदावार होने की वजह से यह निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के तहत किसानों को परिवहन के पहले क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और पटवारी को लिखित सूचना देनी होगी कि वे अपना गन्ना जिले के बाहर किस शक्कर कारखाने को भेज रहे हैं। गन्ना पहुंचने और कारखाने द्वारा दी गयी जानकारी के बाद उपसंचालक कृषि संबंधित किसान को सिर्फ चैक के जरिये अनुदान का भुगतान करेंगे। जिले में मौजूद शक्कर कारखाने के आरक्षित क्षेत्र का गन्ना अन्य जिलों या अन्य राज्यों में स्थित शक्कर कारखानों को किसानों के जरिये भेजे जाने पर अनुदान दिया जायेगा। गौरतलब है कि यह अनुदान व्यवस्था सिर्फ पैराई मौसम 2007 के बचे हुये समय के लिये लागू रहेगी।

19 मार्च 2007

मध्यप्रदेश में पेट्रोल और डीजल की मात्रा और गुणवत्ता की जांच अब सिर्फ राजपत्रित अधिकारी करेंगे। यह बात सहकारिता एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने भोपाल में कही। श्री भार्गव के ध्यान में यह बात आने पर कि पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की मात्रा और गुणवत्ता की जांच गैर राजपत्रित शासकीय कर्मियों के जरिये किये जाने से भारत सरकार के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में अदालतों में दोषियों को सजा नहीं मिल पाती है, इसके तहत इस आशय के निर्देश जारी किये गये हैं। इससे उपभोक्ता के अधिकारों का जहां संरक्षण होगा वहीं संपूर्ण जांच प्रक्रिया सशक्त होगी।

20 मार्च 2007

मध्यप्रदेश शासन के जरिये तयशुदा महिला नीति के तहत सभी विभागीय नीतियों और योजनाओं में महिलाओं के लिये समान स्तर पर भागीदारी देने की कोशिश की जा रही है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को संगठित करके उनकी आर्थिक गतिविधियों को स्व सहायता समूह के रूप में विकसित करने के बाद सहकारी समितियों में पंजीयन कर

वैधानिक स्वरूप प्रदान किया जायेगा। इसके तहत महिलाओं में जागरूकता और स्वावलम्बन की प्रवृत्ति का विकास होगा। इस बहुउद्देशीय योजना के तहत प्रदेश में दिसंबर 06 तक 2 हजार 503 महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्थायें पंजीकृत की गई हैं।

22 मार्च 2007

राज्य सरकार द्वारा आगामी तीन वर्षों में कृषि उत्पादन दुगुना करने की योजना चलाई जा रही है। इसे सफल बनाने के लिये सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को दिए जाने वाले कृषि ऋणों को अगले तीन वर्षों में दुगुना किये जाने की कार्ययोजना बनाई गई है। वर्ष 2006-07 के लिए सरकार ने खरीफ सीजन में 1700 करोड़ और रबी सीजन के लिए 859 करोड़ का ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। जबकि 31 दिसम्बर तक खरीफ सीजन के लिए 1642 करोड़ रुपये तथा रबी सीजन के लिए 578 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है।

राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक कृषक को उसके धारित भूमि के वितरण एवं विभिन्न एजेंसियों से लिए गए ऋणों और उनके अदायगी का ब्यौरा दर्शाते हुए भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिकाएं प्रदान की जाती हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें ऋण पुस्तिकाएं निःशुल्क दी जाती हैं। जबकि अन्य वर्ग के लोगों को 10 रुपये प्रति ऋण पुस्तिका के मान से राशि लेकर पुस्तिका प्रदान की जाती हैं। इस योजना के तहत अब तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वर्ग के 4 लाख से अधिक हितग्राहियों को ऋण पुस्तिकाएं वितरित की गईं।

24 मार्च 2007

सहकारी बैंकों द्वारा सात प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण देने पर राज्य शासन द्वारा दिये जाने वाले ब्याज अनुदान की राशि 51.18 करोड़ रुपये जारी कर दी। इससे प्रदेश के 32 लाख किसान लाभान्वित होंगे। यह जानकारी सहकारिता मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने भोपाल में सहकारी बैंक की 42वीं वार्षिक साधारण सभा में दी। सात प्रतिशत ब्याज दर सिर्फ अल्पकालीन कृषि ऋणों पर होगी और यह वर्ष 2006-07 में खरीफ तथा रबी फसलों के लिए दी जाएगी, अन्य प्रयोजनों के लिए दिए जाने वाले ऋणों को ब्याज अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह खरीफ वर्ष 2006-07 में पूर्व की अवधि की किसी प्रकार की बकाया अल्पकालीन ऋण वसूल होना शेष है तो ऐसी राशि पर किसी प्रकार का अनुदान देय नहीं होगा। कृषकों को ब्याज अनुदान की पात्रता उनके द्वारा फसल ऋण के आहरण दिनांक से ऋण अदायगी तथा ओव्हर ड्यू की दिनांक तक होगा। ओव्हर ड्यू होने के बाद जिला सहकारी बैंकों, प्राथमिक समितियों द्वारा ऐसे प्रकरणों में व्यावसायिक दर से ब्याज वसूल किया जायेगा।

25 मार्च 2007

राज्य शासन द्वारा विवेकानन्द समूह बीमा योजना का प्रदेश भर में प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है इस योजना के तहत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 18 से 65 वर्ष आयु समूह के व्यक्तियों को प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना के कारण मृत्यु होने या पूर्ण अशक्तता होने या दुर्घटना के कारण दोनों आँख, दो अंग या एक आँख या एक अंग की क्षति होने पर 50 हजार रुपये तथा एक आँख या एक अंग की क्षति होने पर 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा प्रभावित व्यक्ति द्वारा दुर्घटना के कारण अस्पताल या नर्सिंग होम में इलाज कराने पर चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर एक हजार रुपये देने का प्रावधान

है। वर्ष 2005-06 में इस योजना के अंतर्गत 5 करोड़ रुपये का प्रावधान था जिसके विरुद्ध 3 करोड़ 45 लाख रुपये का प्रीमियम कम्पनी को प्रदान किया गया। दिसंबर 2006 तक बीमा कम्पनी द्वारा 532 व्यक्तियों को बीमित राशि प्रदान की गई। वर्ष 2006-07 के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान स्वीकृत है।

26 मार्च 2007

प्रदेश में होम्योपैथिक चिकित्सकों के रिक्त पद शीघ्र भरे जायेंगे। प्रथम चरण में 90 पदों के लिए मंजूरी दी गई है। आने वाले वर्षों में भी यह क्रम जारी रहेगा। राज्य सरकार एलोपैथी चिकित्सा के साथ ही होम्योपैथी एवं अन्य चिकित्सा पद्धतियों को पूरा प्रोत्साहन दे रही है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में रोगी के सम्पूर्ण रोग के उपचार की क्षमताएं मौजूद हैं और इस चिकित्सा पद्धति ने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। मुख्यमंत्री भोपाल स्थित समन्वय भवन में होम्योपैथी पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे।

27 मार्च 2007

आदिम जाति कल्याण, ग्रामोद्योग तथा उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री कुंवर विजय शाह ने कहा कि प्रदेश में छात्रावास भवनों के निर्माण कार्य नई तकनीक से किये जायेंगे, जिससे इन भवनों में विद्यार्थियों को उपयुक्त वातावरण तथा सुविधायें मिल सकें। कुंवर शाह स्थानीय महात्मा ज्योतिराव फुले शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में नवनिर्मित त्रिवेणी कन्या छात्रावास का लोकार्पण कर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 89 लाख 39 हजार रुपये लागत से नवनिर्मित सर्व सुविधायुक्त इस कन्या छात्रावास का लोकार्पण कर सभी को बधाईयां दीं। उन्होंने बताया कि यह भवन नयी तकनीक गुणवत्ता से बनाया गया है। अनुसूचित जनजाति वर्ग की 50 छात्राओं के लिए छात्रावास में आवास, भोजन से लेकर कम्प्यूटर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है।

28 मार्च 2007

वर्ष 2007-08 में नौ करोड़ 29 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत किया गया है। पिछले साल इस योजना के तहत सात करोड़ दो लाख 96 हजार रुपये कन्याओं के विवाह पर खर्च किये गये थे। गौरतलब है कि एक अप्रैल 2006 से शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत राज्य शासन द्वारा गरीब, निराश्रित, परिवारों की विवाह योग्य कन्या, विधवा/परित्यक्ता महिलाओं के सामूहिक विवाह के लिये आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना के तहत विवाह के बाद गृहस्थी में जरूरत के सामान के लिए पांच हजार रुपये की राशि दी जाती है।

29 मार्च 2007

भोपाल में इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस एंड टेक्नालॉजी, बायोटेक्नालॉजी पार्क तथा इन्म्यूवेशन सेंटर की स्थापना के लिये जल्दी ही भूमि आवंटित की जायेगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में जैव प्रौद्योगिकी परिषद की आयोजित एक बैठक में दी। उन्होंने बताया कि इंस्टीट्यूट के लिये हवाई अड्डे के पास तथा पार्क के लिये विश्वविद्यालय के पास जमीन का आवंटन प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में कृषि, स्वास्थ्य तथा उद्योग के क्षेत्र में बायोटेक्नालॉजी क्षेत्र में 35 प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में मध्यप्रदेश के विकास की दृष्टि से जल्दी कदम उठाये जायेंगे।

30 मार्च 2007

मध्यप्रदेश में कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योगों को और बेहतर सुविधायें तय करने के लिये समिति का गठन किया जायेगा। यह फैसला भोपाल में विधानसभा कार्यालय में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक बैठक में लिया गया। समिति में उद्योग, वित्त, वाणिज्यिक कर और कृषि विभागों के प्रतिनिधि रहेंगे। समिति एक महीने के अंदर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उद्योगों में पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिये विभिन्न राज्यों द्वारा दी जा रही सहूलियतों का विवरण भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जिससे राज्य के प्रावधानों में अगर जरूरी हो तो संशोधन किया जा सके।

31 मार्च 2007

कृषि यंत्रों में लकड़ी के इस्तेमाल की जगह अनुदान पर किसानों को प्रदाय किये जाने वाले यंत्रों में इस्पात के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की मुहिम शुरू की गई है। कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत कृषि यंत्रों का निर्माण आधुनिक तथा वैज्ञानिक तरीके से करने पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। किसानों को ऐसे कृषि यंत्र बांटने में मध्यप्रदेश देश में पहले स्थान पर है। अब तक कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ऐसे बैलचलित तथा हस्तचलित 41 हजार 901 कृषि यंत्र किसानों को प्रदाय किये गये हैं। कृषि यंत्रों में लकड़ी के इस्तेमाल को कम करने के तहत ग्रामीण क्षेत्र के कृषि यंत्र बनाने वाले कारीगरों और मिस्त्रियों को भी कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

01 अप्रैल 2007

पिछले तीन सालों में मध्यप्रदेश में 25 हजार किलोमीटर लम्बी सड़कें बनाकर कर इतिहास बनाया है। यह बात लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, आदिम जाति कल्याण एवं श्रम मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने शाजापुर में आमसभा को संबोधित करते हुये कही। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ कर रही है। श्री देवड़ा ने कहा कि प्रदेश एक साल में बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेगा। उन्होंने निर्माण मजदूरों के लिये चलाई जा रही कल्याणकारी योजना, बालिकाओं के लिये इस महीने से लागू हो रही लाड़ली लक्ष्मी योजना का खासतौर पर जिक्र करते हुये फायदा उठाने का आव्हान किया।

02 अप्रैल 2007

मध्यप्रदेश सरकार ने सभी निर्माण विभागों में लागू साख-पत्र व्यवस्था को खत्म कर दिया है। यह बात भोपाल में वित्तमंत्री राघवजी ने कही। उन्होंने कहा कि हाल ही में आयोजित 'मंथन 2007' में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे खत्म करने की घोषणा की थी। राघवजी ने कहा कि साख-पत्र व्यवस्था की जगह एक नयी सरल व्यवस्था लागू की गयी है इसका मकसद तयशुदा आवंटन से ज्यादा खर्च को रोकना भी है। गौरतलब है कि प्रदेश के निर्माण विभागों में साख-पत्र व्यवस्था लागू थी इस व्यवस्था में मुख्य अभियंता द्वारा कार्यपालन यंत्रियों को हर महीने साख-पत्र जारी किये जाते थे, कठिनाई को देखते हुए मुख्यमंत्री ने साख-पत्र व्यवस्था को खत्म कर बजट आवंटन कोषालयों के जरिये करने की नयी व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिये थे।

03 अप्रैल 2007

मध्यप्रदेश देश में पहला ऐसा राज्य है जहां राज्य सरकार छात्राओं को नर्स बनाने के शिक्षण प्रशिक्षण का खर्च खुद उठायेगी साथ ही प्रति छात्रा 50-50 हजार रुपये की राशि भी देगी। यह बात लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अजय विश्नोई ने भोपाल में शिक्षण शुल्क की राशि के चेक प्रायवेट नर्सिंग कॉलेजों को वितरण के दौरान कही। उन्होंने कहा कि प्रायवेट-नर्सिंग कॉलेजों को अपनी स्थिति में सुधार लाकर प्रशिक्षण ले रहे नर्सिंग छात्राओं को गुणवत्तायुक्त शिक्षण-प्रशिक्षण देने पर जोर दिया। श्री विश्नोई ने कहा कि स्टाफ नर्सों की कमी को देखते हुये राज्य सरकार ने यह योजना पिछले साल शुरू की थी।

04 अप्रैल 2007

शक्कर कारखाने के क्षेत्र से अन्य शक्कर कारखानों को किसानों द्वारा गन्ना भेजने पर 25 रुपये प्रति क्विंटल परिवहन अनुदान दिया जायेगा। यह बात किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग द्वारा सभी शक्कर मिलों से भोपाल में कही गयी है। विभाग द्वारा जारी खबरों के मुताबिक वे तब तक गन्ना पेराई कार्य जारी रखें जब तक किसानों द्वारा मिलों को गन्ना पहुंचाया जाता रहेगा। अनुमान के मुताबिक राज्य शासन का अनुमानतः सवा छह करोड़ रुपये का खर्च होगा।

05 अप्रैल 2007

मध्यप्रदेश में पंचायत कर्मियों को अन्य शासकीय कर्मचारियों की तरह समान सहूलियतें मुहैया कराने के साथ ही राज्य सरकार मध्यप्रदेश में चार हजार पंचायत-कर्मियों की भर्ती भी करेगी। यह घोषणा सामाजिक न्याय मंत्री सुश्री कुसुम महदेले ने भोपाल में कही। उन्होंने कहा कि आगामी दो-तीन महीने में स्वतंत्र पंचायत संचालनालय का गठन भी किया जायेगा। सुश्री महदेले ने पंचायत समाज सेवा संगठक का पदनाम बदलने की घोषणा के साथ ही उसे राजपत्रित घोषित किये जाने के संबंध में जरूरी कार्यवाही कराने के प्रति भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि अब जनपद पंचायतों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अनुपस्थिति में पंचायत समाज सेवा संगठक को प्रभार दिया जा सकेगा। सुश्री महदेले ने कहा कि पंचायत शिक्षा समाज संगठक की अनुपस्थिति में ग्राम सहायक कामकाज सम्हालेंगे।

06 अप्रैल 2007

सहकारी क्षेत्र का पूरी तरह विकास कर उसे मजबूत बनाने और इसके जरिये गांव-गांव में रोजगार मुहैया कराने के लिये प्रदेश के छह जिलों के लिये 93 करोड़ 54 लाख 76 हजार रुपये की एकीकृत सहकारी विकास परियोजना स्वीकृत की गई है। यह बात सहकारिता एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने भोपाल में कही। उन्होंने कहा कि एकीकृत सहकारी परियोजना के प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, भारत सरकार को भेजे गये थे। निगम ने हाल ही में 93 करोड़ 54 लाख 76 हजार की छह परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। यह परियोजना विदिशा, उज्जैन, झाबुआ, सागर, सीहोर और मंदसौर में क्रियान्वित की जायेगी।

07 अप्रैल 2007

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जरिये बिजली के अवैध उपयोग की रोकथाम और बिजली के अवैधानिक इस्तेमाल की धरपकड़ का अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। यह बात मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कही है। कंपनी के मुताबिक अवैध उपयोग से कंपनी को राजस्व हानि होती है। इस बारे में कंपनी विद्युत के अवैध इस्तेमाल के बारे में सूचना देने वाले व्यक्ति को राजस्व हानि की वसूली का 8.5 प्रतिशत (साढ़े आठ प्रतिशत) या अधिकतम 7500 रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में दी जायेगी। अवैध उपयोग की जानकारी विद्युत वितरण कंपनी के उच्च पदस्थ

अधिकारियों को टेलीफोन पर दी जा सकती है। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जायेगा। कंपनी ने मीटर पर शक्तिशाली चुम्बक (मैग्नेट) रखकर बिजली के मीटर से छेड़छाड़ करने वालों को चेतावनी देते हुये कहा है कि ऐसे मामलों में बिजली अधिनियम 2003 के तहत सख्त कार्यवाही की जायेगी।

09 अप्रैल 2007

लक्ष्य के तहत मध्यप्रदेश में इस साल तकरीबन पंद्रह लाख अतिरिक्त बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों पर नई पोषण आहार नीति से फायदा पहुंचाया जायेगा। यह जानकारी महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री कुसुम सिंह महदेले ने भोपाल में दी। उन्होंने कहा कि राज्य शासन ने 35 साल के इतिहास में पहली बार नई पोषण आहार नीति के तहत दलिया की जगह लोकल फूड मॉडल के आधार पर खीर-पूड़ी, लड्डू, मठरी वगैरह को शामिल करते हुये तकरीबन 20 तरह के खाद्य पदार्थों (व्यंजन) को शामिल करने का फैसला लिया गया है। सुश्री महदेले ने कहा कि इस परिवर्तितस्वरूप में नई पोषण आहार व्यवस्था पर होने वाले कुल खर्च का पचास प्रतिशत केंद्र सरकार वहन करेगी।

इंदौर ने चार महानगरों को पीछे करते हुये पाइप लाइन से गैस अपने शहर में पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर ली है। डिब्रूगढ़ से मिली जानकारी के मुताबिक इंदौर में पाइप लाइन से गैस पहुंचाने का काम जुलाई से शुरू हो जायेगा। सूत्रों के मुताबिक सी.एन.जी. (कंप्रेस्ड नेचुरल गैस) भी इंदौर में जून से पहले मुहैया हो जायेगी। दोनों गैस को पूरा करने के लिये गेल (गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने ब्ल्यू प्रिंट तैयार कर लिया है।

10 अप्रैल 2007

मछली पालन को बढ़ावा देने के लिये अलग-अलग विभागों से समन्वय कायम करने और उसमें आ रही परेशानियों को दूर करने के मकसद से मंत्रिपरिषद की उपसमिति का गठन किया जायेगा। यह बात मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मछली पालन विभाग की समीक्षा के दौरान कही। इस मौके पर मछलीपालन राज्यमंत्री श्री मोती कश्यप भी मौजूद थे। बैठक में बताया गया कि सिंचाई जलाशयों और ग्रामीण तालाबों के पट्टा आवंटन का हक मत्स्य विभाग को दिया जाना प्रस्तावित है। इससे होने वाली आय से 75 प्रतिशत राशि संबंधित पंचायतों को और 25 प्रतिशत राशि जलाशयों के विकास कार्यों पर खर्च की जायेगी। बैठक में यह भी बताया गया कि मछुआरों की समितियों को जिनमें अनुसूचित जाति की समितियों को 15 हजार रुपये और अनुसूचित जनजाति की समितियों को पट्टावधि में डेढ़ लाख रुपये की सहायता दिये जाने का भी प्रावधान है।

11 अप्रैल 2007

ग्रामीण रोजगार योजना के दूसरे चरण के तहत तेरह नये जिलों को शामिल किये जाने पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री रघुवंश प्रसाद सिंह से नई दिल्ली में मुलाकात कर धन्यवाद दिया। उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से मध्यप्रदेश में इंदिरा आवास योजना के वर्तमान कोटे को बढ़ाने का भी आग्रह किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री श्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिये किये जा रहे कार्यों की तारीफ करते हुये कहा कि न केवल राज्य सरकार ने आवंटित राशि का पूरा इस्तेमाल किया है बल्कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अच्छे परिणाम भी मिले हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित जलाभिषेक अभियान के सार्थक क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों खासकर मालवा के भू-जल स्तर में इजाफा हुआ है।

14 अप्रैल 2007

तालाब गहरीकरण कार्य एक बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी है इसमें समाज के सभी तबकों को आगे आना चाहिये। यह बात मध्यप्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री जयंत मलैया ने दमोह में ऐतिहासिक फुटेरा तालाब के गहरीकरण के उद्‌घाटन के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि गहरीकरण का काम डायमंड सीमेंट फैक्टरी के जरिये किया जायेगा। इसके साथ ही तालाब के गहरीकरण का कार्य में जनभागीदारी भी तय की जायेगी। श्री मलैया ने कहा कि सभी प्राचीन तालाब हमारे पूर्वजों की विरासत हैं। नगर के सभी तालाबों और आसपास के तालाबों के गहरीकरण, पार बंधाई, घाट निर्माण के कार्य प्रमुखता से कराये जायेंगे।

15 अप्रैल 2007

मध्यप्रदेश में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवायें देने के लिये अनेक योजनायें लागू की गई हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन खासतौर पर निर्धन तबके के इलाज में निजी चिकित्सकों तथा निजी अस्पतालों का सहयोग जरूरी है। यह बात मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में नर्सिंग होम एसोसिएशन द्वारा आयोजित आठवीं राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुये कही। उन्होंने कहा कि निजी नर्सिंग होम की व्यावसायिक समस्याओं के निराकरण के लिये राज्य सरकार जरूरी कदम उठायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में मातृ-मृत्यु दर और शिशु-मृत्यु दर कम करने के साथ ही महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की स्थिति खत्म करने के लिये लगातार कोशिश की जा रही है।

16 अप्रैल 2007

मध्यप्रदेश के श्रमिकों के फायदे के लिये हर मुमकिन कोशिश की जायेगी। यह बात मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सभी श्रेणी के मजदूरों को तकलीफों से निजात मिल सके इसलिये सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है तथा समाधान के लिये समिति गठित की जायेगी। सफाई कामगार आयोग बनाने के लिये तो राज्य सरकार प्रतिबद्ध है ही, उद्योगों की स्थापना से प्रभावित होने वालों के लिये बेहतर मुआवजे का इंतजाम भी किया जायेगा।

17 अप्रैल 2007

संजय गांधी ताप विद्युत गृह विस्तार इकाई जून में और अमरकंटक विस्तार इकाई का कार्य अगस्त 07 में पूरा होने के बाद 710 मेगावाट ज्यादा बिजली पैदा हो सकेगी। यह बात ऊर्जा मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने भोपाल में कही। उन्होंने बिजली की मांग और उपलब्धता के फर्क को कम करने के लिये विद्युत उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि बिजली के अनावश्यक इस्तेमाल पर अंकुश लगाकर औद्योगिक क्षेत्र में 20 से 26 प्रतिशत, कृषि क्षेत्र में 25 से 30 प्रतिशत, घरेलू और वाणिज्यिक क्षेत्र में 15 से 20 प्रतिशत तथा स्ट्रीट लाईट और जलकल में 5 से 10 प्रतिशत तक बिजली की बचत की जा सकती है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 6109 मेगावाट की अधिकतम मांग की आपूर्ति की गई है यह स्थिति पूर्व वर्षों की तुलना में बेहतर है।

20 अप्रैल 2007

मध्यप्रदेश में बायोगैस कार्यक्रम के तहत इस साल 9522 बायोगैस संयंत्र लगाये गये हैं। इस तरह से अब तक कुल एक लाख 65 हजार 458 बायोगैस संयंत्र स्थापित किये गये हैं। यह संयंत्र एम.पी. एग्रो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के जरिये लगाये गये हैं। प्रदेश में खासतौर पर तीन तरह के बायोगैस संयंत्र लगाये जा रहे हैं इनमें तैरते हुए होल्डर वाला के.व्ही.आई.सी. प्रकार का संयंत्र, स्थित गुंबदवाला जनता मॉडल और संशोधित स्थित गुंबद वाला दीनबंधु संयंत्र है।

21 अप्रैल 2007

मध्यप्रदेश के वन ग्रामों में अधोसंरचना विकास के लिये तैयार की गई योजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। यह योजना वन मंत्री हिम्मत कोठारी की पहल पर तैयार की गई। वन मंत्री ने निर्देश दिये हैं कि वन ग्रामों में निवास कर रहे ग्रामीणों को विकास की मुख्य धारा में लाते हुये उनका समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास किया जाये। इन्हीं निर्देशों के तहत वन विभाग द्वारा अलग से एक नयी योजना स्वीकृति के लिये केंद्र सरकार के सामने रखी गई। इस योजना में 867 वन ग्रामों में अवशेष अधोसंरचना विकास कार्यों के प्रस्ताव दिये गये थे। इस स्वीकृति के तहत 867 वन ग्रामों में करीब 130 करोड़ रुपये के विकास कार्य किये जायेंगे। गौरतलब है कि पूर्व में भी इन्हीं वन ग्रामों के विकास के लिये लगभग 130 करोड़ रुपये की योजनायें स्वीकृत की गई थीं, जिनके तहत विभिन्न विकास कार्य प्रगति पर हैं।

22 अप्रैल 2007

दो हजार आश्रमों और छात्रावासों में आगामी तीन सालों में शत-प्रतिशत स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता रेन वॉटर हार्वेस्टिंग तथा जल का दोबारा इस्तेमाल जैसे उपायों को लागू किया जायेगा। यह फैसला यूनिसेफ और आदिम जाति कल्याण विभाग के संयुक्त स्वच्छ पेयजल अभियान के तहत भोपाल में आदिवासी विकास विभाग के आयुक्त श्री राघव चन्द्रा की मौजूदगी में लिया गया। श्री राघव चन्द्रा ने बताया कि वर्ष 2007-08 में इस योजना के प्रथम चरण में 100 आश्रमों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना पर तीन करोड़ रुपये खर्च होंगे। योजना से तकरीबन पांच हजार छात्र-छात्राओं को फायदा होगा। श्री राघव चन्द्रा ने कहा कि इस योजना के तहत बाकी शालाओं को 2010 तक शामिल किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

23 अप्रैल 2007

इस साल 94 हजार हेक्टर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। यह बात नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री उदय वर्मा ने इंदौर में कही। उन्होंने प्राधिकरण के इंजीनियरों से कहा कि योजना बनाने पर खासतौर पर ध्यान दीजिये क्योंकि अच्छी योजना से ही कामयाबी मिलती है। श्री वर्मा ने निर्माण की गुणवत्ता पर भी ध्यान देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता के प्रति जागरूकता सभी स्तरों पर इंजीनियरों के कार्य में दिखाई देना चाहिये। उन्होंने कहा कि उपयंत्रियों को तकनीकी रूप से दक्ष होना चाहिये क्योंकि यह निर्माण प्रक्रिया की खास कड़ी हैं।

24 अप्रैल 2007

मध्यप्रदेश में खनिज विभाग द्वारा खनिज पट्टों के आवंटन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। मध्यप्रदेश में घोषित महिला नीति के पालन के तहत यह आवंटन किया जा रहा है। वर्ष 2006-07 में 510 महिलाओं को खनिज उत्खनन के पट्टे दिये गये। इनमें पांच खनिज उत्खनन के पट्टे महिलाओं को व्यक्तिगत नाम से भी आवंटित किये गये।

25 अप्रैल 2007

31 मई के बाद भी अगर किसी क्षेत्र में गन्ना बचेगा तो शक्कर मिलों में उत्पादन जारी रखे जाने के संबंध में व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी ताकि किसानों को किसी तरह का नुकसान नहीं हो। यह बात मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गन्ना उत्पादक किसानों की समस्याओं के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि आगामी सीजन के पहले गन्ना नीति बनायी जायेगी। गन्ना उत्पादक किसानों और शक्कर तथा खांडसारी उत्पादकों के हितों का भी ख्याल रखते हुये इसे अंतिम रूप दिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में आवश्यक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये जिससे किसानों और शक्कर मिलों दोनों पक्षों को कोई कठिनाई नहीं हो।

27 अप्रैल 2007

पिछले साल की तुलना में इस साल गन्ने की फसल और उत्पादकता दोनों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। यह बात मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कही। उन्होंने गन्ना उत्पादक किसानों के नाम अपने एक संदेश में कहा कि प्रदेश सरकार ने गन्ना उत्पादक किसानों के हित में चीनी मिलों को 31 मई तक पैराई जारी रखने को कहा है ताकि किसान उन्हें ताजा गन्ना बेच सकें। गौरतलब है कि किसानों का गन्ना सुव्यवस्थित ढंग से कारखानों तक पहुंचे इसके लिये प्रदेश सरकार ने प्रशासकीय स्तर पर कलेक्टर, कृषि विभाग के उपसंचालक और चीनी कारखानों के प्रबंधक को संयुक्त रूप से पर्ची के वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। हर पर्ची पर मिल द्वारा गन्ना लेने की तारीख अंकित की जायेगी।

27 अप्रैल 2007

केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय ने मध्यप्रदेश में चार बहुउद्देश्यीय सांस्कृतिक परिसर खोलने का फैसला किया है। इसमें से अब तक तीन पर काम शुरू हो गया है। यह बात पर्यटन मंत्री अंबिका सोनी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगा ही, रोज़गार के मौके भी मिलेंगे।

28 अप्रैल 2007

राज्य शासन के जरिये विजयाराजे जननी कल्याण बीमा योजना के तहत मई 2006 से 28 फरवरी 2007 के दौरान एक लाख 18 हजार 520 हितग्राहियों को फायदा पहुंचा है। शासकीय अस्पतालों में प्रसव कराने वाली गरीब महिलाओं में से 50 प्रतिशत से ज्यादा महिलाओं ने इस योजना का फायदा उठाया है। गौरतलब है कि शासन द्वारा 12 मई 2006 से विजयाराजे जननी कल्याण बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से शासकीय अस्पतालों में प्रसव कराने वाली गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को एक हजार रुपये तक की राशि औषधि वगैरह की प्रतिपूर्ति के लिये दी जाती है। यह राशि इन महिलाओं को बीमा कम्पनी के जरिए दी जाती है।

29 अप्रैल 2007

मध्यप्रदेश में विकास और जनकल्याण का नया माहौल बना है जिसमें विकास को जनान्दोलन के रूप में लिया गया है। यह बात मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में बाईपास मार्ग के लोकार्पण के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि विन्ध्य क्षेत्र अब विकास की दौड़ में सबसे आगे रहेगा इसके लिये जरूरी मूलभूत सहूलियतें मुहैया कराई जायेंगी। 48 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 19.44 किलोमीटर लम्बे बाईपास के लोकार्पण के मौके पर उन्होंने कहा कि रीवा को विकसित और खुशहाल बनाने के लिये हर मुमकिन कोशिश की जायेगी।

01 मई 2007

कृषि विभाग को आगामी खरीफ फसल में किसानों को खाद और अच्छा बीज तथा सहकारिता विभाग को पूरी तरह से ऋण मुहैया कराने के निर्देश दिये हैं। यह निर्देश मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में खरीफ फसलों के लिये तैयारी की समीक्षा के दौरान दिये। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अभी तक डी.ए.पी. खाद के आयात की नीति की घोषणा नहीं की है। श्री सिंह ने कहा कि केन्द्र से अभी से आगामी खरीफ फसल के लिये पर्याप्त खाद आवंटन का अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री ने बैठक में अमानक स्तर के बीज की बिक्री के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इसके लिये कृषि विभाग द्वारा नमूने लेने और निरीक्षण की कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

02 मई 2007

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुनसिंह से मुलाकात कर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने के बारे में जल्दी ही कार्यवाही करने का निवेदन किया। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन (नेक) बंगलौर के जरिये डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय का पुनर्मूल्यांकन किया गया था जिसके मुताबिक विश्वविद्यालय को ग्रेड-ए हासिल हुआ। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की ओर से विश्वविद्यालय के पुनर्मूल्यांकन के लिये प्रवर समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह स्वीकार किया कि विश्वविद्यालय ने पहले मूल्यांकन के बाद सभी दिशाओं में सराहनीय प्रगति की है।

03 मई 2007

मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति तथा प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड द्वारा पंजीकृत चिकित्सकों को परिचय पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। बोर्ड ने पंजीकृत चिकित्सकों से कहा गया है कि वे अपने पते में किसी भी तब्दीली की यथा समय सूचना बोर्ड को दें। यह सूचना दिया जाना मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम के तहत अनिवार्य है। इसी तरह से ऐसे पंजीकृत चिकित्सक जिनके मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र में फोटो नहीं है, उनके प्रमाण पत्रों पर फोटो चस्पा कर सत्यापित किये जा रहे हैं। इसके लिये अंतिम तिथि 30 जुलाई तय की गई है।

04 मई 2007

सागर के डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय को प्रदेश का केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित करने के लिये एक प्रस्ताव केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजने के निर्देश दिये गये हैं। यह निर्देश राज्यपाल डॉ. बलराम जाखड़ ने भोपाल में डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. धीरेन्द्रपाल सिंह को विश्वविद्यालय की उपलब्धियों पर बधाई देने के दौरान

दिये। गौरतलब है कि सागर का यह विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जिसने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा पुनर्मूल्यांकन में यह उपलब्धि हासिल की है। 'ए' ग्रेड हासिल करने के साथ ही यह विश्वविद्यालय मद्रास और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जैसे श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के समान उच्च शिक्षा संस्थानों में शामिल हो गया है।

06 मई 2007

राज्य सरकार समाज के उस वर्ग को जायज हक दिलाने के लिये लगातार कोशिश कर रही है जिससे वह अब तक महरूम है। यह बात मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह ने भोपाल में मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ (अजाक्स) की जिला शाखा द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुये कही। उन्होंने कहा कि सामाजिक समानता के लिये शोषित रहे वर्ग को आरक्षण और ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें जरूर देना चाहिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में पहली बार पूरे प्रदेश से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को भोपाल में आमंत्रित कर पंचायत का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में अनुसूचित जाति कल्याण की 54 घोषणायें की गईं जिन पर अमल हो रहा है।

07 मई 2007

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति अब महंगाई बढ़ने के साथ ही बढ़ती जायेगी। यह बात मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा आयोजित ऋण वितरण समारोह को संबोधित करते हुये कही। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति पंचायत में लिये गये फैसलों के आधार पर विद्यार्थियों को दी जाने वाले छात्रवृत्ति बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने समाज के सभी वर्गों की तकलीफ को समझकर उनके समाधान को प्राथमिकता से शुरू किया है। इसके लिये विभिन्न वर्गों की पंचायतें आयोजित की गयी हैं।

08 मई 2007

मध्यप्रदेश शासन ने आदिवासियों के संदिग्ध जिम्मेदारियों के निवारण योजना के क्रियान्वयन के लिये वित्तीय वर्ष में दस लाख रुपये का प्रावधान किया है। आदिवासी बाहुल्य 19 जिलों के 89 विकासखंडों के लिये वर्ष 2007-08 में 6.23 लाख रुपये राशि का आवंटन भी जारी किया जा चुका है। गौरतलब है कि अनुसूचित क्षेत्रों में विभिन्न शासकीय और अर्द्ध शासकीय संस्थाओं के जरिये हितग्राहीमूलक कार्यक्रम के तहत योजना की असफलता या योजना का फायदा मिलने पर भी आदिवासियों पर अनजाने और अनचाहे ऋणों की जिम्मेदारी डाल दी जाती है। ऐसे संदिग्ध दायित्वों के निराकरण के लिये 'मध्यप्रदेश अनुसूचित क्षेत्र दायित्व निर्धारण नियम, 1979 यथा संशोधित नियम 2003' लागू किये गये हैं।

09 मई 2007

मध्यप्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का नागरिकों के लिये बेहतर उपयोग करने पर ध्यान दिया जाये। यह बात मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (मेपकास्ट) के जरिये शुरू किये गये एडूसेट नेटवर्क का शुभारंभ करते हुये कही। उन्होंने कहा कि विज्ञान प्रसार के लिये यह शुरूआत खास है। गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिये यह ऐसी तकनीक है जिससे कम साधनों में प्रभावी ढंग से शिक्षा दी जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि

जरूरत इस बात की है कि आम आदमी खासतौर पर उपेक्षित वर्ग को नई तकनीक का पूरा फायदा मिले और जहां अभी भी अंधेरा है वहां हम विज्ञान का दीप जलायें।

12 मई 2007

मध्यप्रदेश शासन ने शहर के उन हिस्सों को जो पानी की कमी से दो चार हो रहे हैं उन क्षेत्रों में पेयजल परिवहन के लिये इस वित्तीय वर्ष में सात करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। राहत आयुक्त द्वारा जारी आवंटन आदेश के मुताबिक यह राशि प्रदेश के सभी 48 जिलों के नगरीय निकायों के इस्तेमाल के लिये संबंधित जिला कलेक्टरों को भेजी गयी है। आदेश के मुताबिक नगर निगम ग्वालियर को 15 लाख रुपये, भोपाल को दस लाख, मुड़वारा (कटनी) को 8 लाख रुपये, सतना को 8 लाख रुपये, रीवा को 6 लाख और जबलपुर को साढ़े चार लाख रुपये की राशि आवंटित की गयी है। 14 नगर निगमों को कुल 71 लाख 50 हजार रुपये की राशि आवंटित की गयी है।

14 मई 2007

मध्यप्रदेश में सहकारिता विभाग में महत्वपूर्ण शीर्षस्थ सहकारी संस्थाओं और जिला तथा राज्य स्तर के विभागीय कार्यालयों को सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ने की योजना का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में विभागीय जिला कार्यालयों को कम्प्यूटर उपलब्ध करा दिये गये हैं। समस्त जिला कार्यालयों के स्टाफ को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यालय स्तर पर सतत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। शासन द्वारा लागू की जाने वाली ई-गवर्नेन्स की योजना के क्रियान्वयन के लिये भी प्रयास जारी हैं।

15 मई 2007

मध्यप्रदेश में स्वजल धारा कार्यक्रम के तहत-2803 जलप्रदाय योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। स्वजल धारा कार्यक्रम वर्ष 2006-07 के लिये है। इस कार्यक्रम में ग्रामवासियों के फैसले के मुताबिक योजनाओं का क्रियान्वयन ग्रामीणों की ग्राम जल और स्वच्छता समितियों के जरिये किया जाता है। इस योजना के तहत 40 लीटर प्रतिव्यक्ति रोज के हिसाब से जल प्रदाय का इंतजाम किया जाता है। गौरतलब है कि दस प्रतिशत राशि जनसहयोग के रूप में तथा 90 प्रतिशत राशि केंद्र के जरिये मुहैया कराई जाती है। योजना के पूरे हो जाने पर इनके संचालन और संधारण की जिम्मेदारी ग्राम समिति की होती है।

16 मई 2007

मध्यप्रदेश में तेन्दूपत्ता संग्रहण की तेजी का यह आलम है कि 15 मई तक राज्य के अलग-अलग केंद्रों पर कुल पांच लाख नब्बे हजार 296 मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण हो चुका है। यह बात मध्यप्रदेश राज्य सहकारी लघु वनोपज संघ के एम.डी. श्री रमेश दवे ने भोपाल में कही। उन्होंने कहा कि मौजूदा सीजन में तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्यों से वनवासियों को एक लाख 16 हजार से ज्यादा मानव दिवस का रोजगार मिल चुका है। श्री दवे ने बताया कि तेन्दूपत्ता संग्रहण के तहत पिछले साल 15 मई तक दो लाख 24 हजार 970 मानक बोरा पत्ता जमा हुआ था।

17 मई 2007

राज्य सरकार स्व-सहायता समूहों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिये हर मुमकिन कोशिश करेगी। यह बात पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रुस्तम सिंह ने भोपाल में 'लघु ऋण- चुनौतियां और अवसर' विषय पर आयोजित दो

दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुये कही। उन्होंने स्व-सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर देते हुये कहा कि स्व-सहायता समूहों को क्रेडिट सहायता देने से वे गरीब परिवारों के लिये आजीविका निर्माण करने में सक्षम बनेंगे। श्री सिंह ने कहा कि नौकरी और आजीविका में फर्क है। स्व-सहायता समूह बड़ी संख्या में गरीब परिवारों के लिये आजीविका का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब राज्य में स्व-सहायता समूहों को लघु स्तर पर आर्थिक गतिविधियां लागू करने की जिम्मेदारी दी जा रही है।

18 मई 2007

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के तहत 18 जिलों में विद्युत वितरण प्रणाली के उन्नयन के लिये एशियाई विकास बैंक के जरिये ऋण प्राप्त कर विकास कार्य को अंजाम दिया जायेगा। एशियाई विकास बैंक के जरिये मध्यप्रदेश पॉवर सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के डिस्ट्रीब्यूशन कम्पोनेंट (वितरण घटक) में जो ऋण हासिल किया गया है इसके तहत कम्पनी आगामी पांच साल में 960 करोड़ रुपये के कार्य करेगी। तीन चरणों में होने वाले कार्य के तहत एशियाई विकास बैंक की मदद से 129 मिलियन डॉलर खर्च कर निर्माण कार्य किये जायेंगे। भोपाल में हुई बैठक में तय किया गया कि इन सभी कार्यों से जहां एक ओर विद्युत उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति तय की जायेगी वहीं दूसरी तरफ उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिये उपभोक्ता सेवा केंद्र की अवधारणा भी क्रियान्वित की जायेगी।

19 मई 2007

मध्यप्रदेश सरकार आदिवासी विद्यार्थियों में मौजूद खेल प्रतिभा को विकसित करने के इरादे से प्रदेश में दो नवीन क्रीड़ा-परिसरों की स्थापना करने जा रही है। बैतूल और खंडवा जिले के खालवा में स्थापित किये जा रहे खेल परिसर में अत्याधुनिक खेल सुविधा के साथ कोच और खेल अनुदेशकों का भी इंतजाम किया जा रहा है। तीन-तीन करोड़ की लागत से बनने जा रहे खेल परिसर में 100 सीट्स का आवासीय भवन, कोच, पी.टी.आई. और कर्मचारियों के लिये आवास गृह, खेल मैदान और ट्रेक का निर्माण किया जायेगा।

20 मई 2007

मध्यप्रदेश में इस साल साढ़े छह सौ से ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्र भवनों का निर्माण होगा। 12 करोड़ 79 लाख 83 हजार रुपये से इन भवनों का निर्माण होगा। प्रदेश में 367 समेकित बाल विकास परियोजनाओं के तहत 59 हजार 324 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किये जा रहे हैं। मौजूदा दौर में 14 हजार दो सौ आंगनवाड़ी केंद्रों के अपने भवन हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों के बेहतर संचालन के लिये उनके भवनों के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है।

21 मई 2007

मध्यप्रदेश के वन प्रबंधन में भी सूचना प्रौद्योगिकी और उन्नत तकनीकों के इस्तेमाल से वनों के विकास और सुरक्षा गतिविधियों के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। यह बात वनमंत्री श्री हिम्मत कोठारी ने भोपाल में वन विभाग द्वारा स्थापित 'मध्यप्रदेश वन सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्र' के शुभारंभ के मौके पर कही। उन्होंने इस आधुनिकतम प्रशिक्षण केंद्र की विशेषताओं का जायजा लेते हुये उम्मीद जताई कि विभागीय अधिकारी और कर्मचारी यहां प्रशिक्षण हासिल करके

अपनी जिम्मेदारी का अच्छी तरह पालन करेंगे। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश वन सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्र में प्लाज्मा टी.व्ही. और एल.सी.डी. मॉनिटर वाले कम्प्यूटर मुहैया कराये गये हैं। यह केंद्र पूरी तरह से वाई-फाई सुविधायुक्त है इसके साथ ही यहां विदाउट वायर कनेक्टिविटी इंटरनेट सुविधा है।

22 मई 2007

मध्यप्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ाने के मकसद से क्वालिटी मॉनीटर का इन्तजाम करने जा रही है। इसके तहत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा एवं नर्सिंग प्रशिक्षण और शैक्षणिक संस्थाओं में गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जायेगा। क्वालिटी मॉनीटर के लिये राज्य शासन ने विशेषज्ञों के चयन की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्वालिटी मॉनीटर के लिये विशेषज्ञों के चयन में सेवानिवृत्त 65 साल तक के अधिकारियों को प्राथमिकता दी जायेगी। खासतौर पर इसमें चिकित्सक, चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग प्रशिक्षण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और लोक निर्माण विभाग, प्रशासन से जुड़े रहे राजपत्रित अधिकारियों को जगह दी जायेगी।

23 मई 2007

अन्य राज्यों की तरह मध्यप्रदेश में भी नर्सिंग सेवा को और बेहतर बनाया जायेगा। यह बात लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अजय विश्नोई ने भोपाल में नर्सिंग शिक्षा और सेवा विषय पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में शासकीय और निजी भागीदारी से 38 नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं। सरकार नर्सिंग के क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के पक्ष में है। श्री विश्नोई ने कहा कि नर्स प्रशिक्षण के लिये मध्यप्रदेश की बालिकाओं को ही नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश मिले ऐसी कोशिश की जायेगी। नर्सिंग केडर को और बेहतर बनाने के लिये पश्चिम बंगाल की प्रणाली को अपनाने पर सरकार विचार कर रही है।

24 मई 2007

मध्यप्रदेश में किसानों को खरीफ सीजन में रासायनिक खादों की आपूर्ति वक्त पर हो इसके लिये चाक चौबंद इंतजाम किये जा रहे हैं। यह बात मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के अध्यक्ष श्री रमाकांत भार्गव ने भोपाल में कही। उन्होंने कहा कि राज्य शासन के निर्देश पर विपणन संघ ने प्रदेश की सहकारी समितियों में सभी तरह की रासायनिक खादों का अग्रिम भण्डारण करने का इंतजाम किया है। प्रदेश में यूरिया, डी.ए.पी. और सुपर फास्फेट खादों की बढ़ती मांग को देखते हुये विपणन संघ ने अपने नगद खाद विक्रय केंद्रों से किसानों को सभी तरह की रासायनिक खादें मुहैया कराने का इंतजाम किया है।

25 मई 2007

मध्यप्रदेश शासन द्वारा एम.सी.आई. के मापदंड के मुताबिक प्रदेश के मेडीकल कॉलेजों के लिये तीन हजार 403 पदों की संस्थावार और विषयवार स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य शासन द्वारा स्वीकृत 2500 नर्सिंग संवर्ग के पदों का बंटवारा इस तरह किया गया है। मेडीकल कॉलेज भोपाल में पांच सौ, इंदौर में छह सौ, जबलपुर में पांच सौ, ग्वालियर में पांच सौ और रीवा में चार सौ पद स्वीकृत किये गये हैं।

19 मई 2007

मध्यप्रदेश सरकार आदिवासी विद्यार्थियों में मौजूद खेल प्रतिभा को विकसित करने के इरादे से प्रदेश में दो नवीन क्रीड़ा-परिसरों की स्थापना करने जा रही है। बैतूल और खंडवा जिले के खालवा में स्थापित किये जा रहे खेल परिसर में अत्याधुनिक खेल सुविधा के साथ कोच और खेल अनुदेशकों का भी इंतजाम किया जा रहा है। तीन-तीन करोड़ की लागत से बनने जा रहे खेल परिसर में 100 सीट्स का आवासीय भवन, कोच, पी.टी.आई. और कर्मचारियों के लिये आवास गृह, खेल मैदान और ट्रेक का निर्माण किया जायेगा।

20 मई 2007

मध्यप्रदेश में इस साल साढ़े छह सौ से ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्र भवनों का निर्माण होगा। 12 करोड़ 79 लाख 83 हजार रुपये से इन भवनों का निर्माण होगा। प्रदेश में 367 समेकित बाल विकास परियोजनाओं के तहत 59 हजार 324 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किये जा रहे हैं। मौजूदा दौर में 14 हजार दो सौ आंगनवाड़ी केंद्रों के अपने भवन हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों के बेहतर संचालन के लिये उनके भवनों के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है।

21 मई 2007

मध्यप्रदेश के वन प्रबंधन में भी सूचना प्रौद्योगिकी और उन्नत तकनीकों के इस्तेमाल से वनों के विकास और सुरक्षा गतिविधियों के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। यह बात वनमंत्री श्री हिम्मत कोठारी ने भोपाल में वन विभाग द्वारा स्थापित 'मध्यप्रदेश वन सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्र' के शुभारंभ के मौके पर कही। उन्होंने इस आधुनिकतम प्रशिक्षण केंद्र की विशेषताओं का जायजा लेते हुये उम्मीद जताई कि विभागीय अधिकारी और कर्मचारी यहां प्रशिक्षण हासिल करके अपनी जिम्मेदारी का अच्छी तरह पालन करेंगे। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश वन सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्र में प्लाज्मा टी.व्ही. और एल.सी.डी. मॉनिटर वाले कम्प्यूटर मुहैया कराये गये हैं। यह केंद्र पूरी तरह से वाई-फाई सुविधायुक्त है इसके साथ ही यहां विदाउट वायर कनेक्टिविटी इंटरनेट सुविधा है।

22 मई 2007

मध्यप्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ाने के मकसद से क्वालिटी मॉनीटर का इन्तजाम करने जा रही है। इसके तहत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा एवं नर्सिंग प्रशिक्षण और शैक्षणिक संस्थाओं में गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जायेगा। क्वालिटी मॉनीटर के लिये राज्य शासन ने विशेषज्ञों के चयन की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्वालिटी मॉनीटर के लिये विशेषज्ञों के चयन में सेवानिवृत्त 65 साल तक के अधिकारियों को प्राथमिकता दी जायेगी। खासतौर पर इसमें चिकित्सक, चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग प्रशिक्षण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और लोक निर्माण विभाग, प्रशासन से जुड़े रहे राजपत्रित अधिकारियों को जगह दी जायेगी।

23 मई 2007

अन्य राज्यों की तरह मध्यप्रदेश में भी नर्सिंग सेवा को और बेहतर बनाया जायेगा। यह बात लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अजय विश्नोई ने भोपाल में नर्सिंग शिक्षा और सेवा विषय पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में शासकीय और निजी भागीदारी से 38 नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं। सरकार नर्सिंग के क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के पक्ष में है। श्री विश्नोई ने कहा कि नर्स प्रशिक्षण के लिये मध्यप्रदेश की

बालिकाओं को ही नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश मिले ऐसी कोशिश की जायेगी। नर्सिंग केडर को और बेहतर बनाने के लिये पश्चिम बंगाल की प्रणाली को अपनाने पर सरकार विचार कर रही है।

24 मई 2007

मध्यप्रदेश में किसानों को खरीफ सीजन में रासायनिक खादों की आपूर्ति वक्त पर हो इसके लिये चाक चौबंद इंतजाम किये जा रहे हैं। यह बात मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के अध्यक्ष श्री रमाकांत भार्गव ने भोपाल में कही। उन्होंने कहा कि राज्य शासन के निर्देश पर विपणन संघ ने प्रदेश की सहकारी समितियों में सभी तरह की रासायनिक खादों का अग्रिम भण्डारण करने का इंतजाम किया है। प्रदेश में यूरिया, डी.ए.पी. और सुपर फास्फेट खादों की बढ़ती मांग को देखते हुये विपणन संघ ने अपने नगद खाद विक्रय केंद्रों से किसानों को सभी तरह की रासायनिक खादें मुहैया कराने का इंतजाम किया है।

25 मई 2007

मध्यप्रदेश शासन द्वारा एम.सी.आई. के मापदंड के मुताबिक प्रदेश के मेडीकल कॉलेजों के लिये तीन हजार 403 पदों की संस्थावार और विषयवार स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य शासन द्वारा स्वीकृत 2500 नर्सिंग संवर्ग के पदों का बंटवारा इस तरह किया गया है। मेडीकल कॉलेज भोपाल में पांच सौ, इंदौर में छह सौ, जबलपुर में पांच सौ, ग्वालियर में पांच सौ और रीवा में चार सौ पद स्वीकृत किये गये हैं।

26 मई 2007

सभी समाज के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। यह बात मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के युवक-युवती परिचय सम्मेलन को संबोधित करते हुये कही। उन्होंने कहा कि अन्य समाजों के साथ सवर्ण समाज में भी आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, जिनके आर्थिक उत्थान के लिये हम प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सभी गरीब बेटियों की शादी सरकार के जरिये कराई जा रही है, जिससे बेटी माँ-बाप के लिये बोझ न बने। उन्होंने कहा कि जो भी अभिभावक अपनी बेटियों की शादी करने में असमर्थ होंगे उन सभी का विवाह शासन करायेगा। लड़कियों की संख्या में लगातार हो रही कमी पर चिंता जताते हुये उन्होंने कहा कि इस साल पूरे प्रदेश में अब तक तकरीबन तीस हजार विवाह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत संपन्न हो चुके हैं।

27 मई 2007

खनिज राजस्व आय बढ़ाने के लिये जिला खनिज अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में नई खदानें घोषित कराने और जिन खदानों में खनिज उत्खनन का कार्य ठेकेदार के जरिये धीरे किया जा रहा हो तो उन खदानों की लीज खत्म करके नीलामी की कार्यवाही की जायेगी। यह बात खनिज संसाधन एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने पन्ना में खनिज अधिकारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुये कही। उन्होंने अधिकारियों को खनिज की चोरी रोकने के लिये लगातार खदान स्थलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिये।

28 मई 2007

मध्यप्रदेश सरकार गांव और गरीब किसानों के हित संवर्द्धन के लिए दृढ़ संकल्पित है। यह अहसास पहली बार जनता को वर्तमान सरकार ने दिलाया है। उक्त उद्‌गार वन एवं परिवहन मंत्री श्री हिम्मत कोठारी ने मंदसौर जिले के सीतामऊ विकासखंड में विभिन्न ग्रामों में आयोजित कार्यक्रमों में व्यक्त किये। इस दौरान प्रभारी मंत्री श्री हिम्मत कोठारी ने सीतामऊ विकासखण्ड के अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में जिला प्रभारी मंत्री श्री कोठारी ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि गांवों के विकास से ही प्रदेश का विकास जुड़ा हुआ है। प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 22 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ। अगले दो वर्षों में 12 हजार किलोमीटर और सड़क निर्माण की योजना है। राज्य सरकार ने किसानों के हित में कई निर्णय लिये हैं। अब किसानों को सहकारी बैंकों से सात प्रतिशत वार्षिक दर पर ऋण मिल रहा है। पहले इसकी ब्याज दर 14 प्रतिशत थी। किसानों के हित में ब्याज का अंतर सरकार वहन करेगी।

29 मई 2007

मध्यप्रदेश में नई दवा-नीति के लागू होने से सभी जरूरी दवाईयां पूरी तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक सुनिश्चित होंगी। यह बात लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अजय विश्नोई ने सिवनी में जिला चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान कही। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सिवनी के पांच आदिवासी विकासखंडों में दीनदयाल चलित अस्पताल की सहूलियत हो जायेगी। श्री विश्नोई ने कहा कि इसमें डॉक्टर और स्टॉफ नर्स रहेंगी तथा प्रसव पूर्व जांच और खून वगैरह की जांच की भी सहूलियत रहेगी। उन्होंने कहा कि मोबाइल क्लीनिक से जिले के दूर के गांवों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें सुनिश्चित होंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रसूता महिलाओं को अस्पताल से छुट्टी के साथ जननी सुरक्षा योजना का चैक मिल जाना चाहिये। अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं हुआ तो सिविल सर्जन को इसके लिये जिम्मेदार माना जायेगा।

30 मई 2007

मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जल अभिषेक अभियान के तहत जल प्रदाय योजनाओं के संधारण और गुणवत्तापूर्ण पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये युद्ध स्तर पर मुहिम जारी है। राज्य के सभी नगरीय निकायों में जल स्रोतों, जल संरचनाओं, जल प्रदाय उपकरणों और मशीनों की साफ-सफाई और पेंटिंग तथा आईलिंग करने के साथ ही काम करने की तारीख भी लिखी जा रही है, जिससे तयशुदा समय में पूरा होते ही दोबारा यह कार्य किया जायेगा। नगरीय जल प्रदाय के जल स्रोतों को प्रदूषण से मुक्त करने के लिये इन स्रोतों में जमा दूषित जल, कचरे तथा गंदगी की रोकथाम के लिये भी नियमित रूप से कार्यवाही की जा रही है।

30 मई 2007

मध्यप्रदेश के बड़वानी और डिंडोरी में दो नये केंद्रीय विद्यालय खोले जायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने देश में पचास नये केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की थी। यह सभी विद्यालय एक अप्रैल से शुरू होने थे। इनका अस्थाई भवनों में संचालन का प्रावधान रखा गया है। इसके लिये वर्ष 2010 तक स्थाई भवन बनवाने का आश्वासन केंद्र ने

दिया है। विशेष फोकस क्षेत्र के तहत 20 राज्यों को शामिल किया गया है इनमें मध्यप्रदेश भी शामिल है। यह सभी विद्यालय चालू शैक्षणिक सत्र वर्ष 2007-08 के तहत खोले जायेंगे।

31 मई 2007

मध्यप्रदेश शासन ने शैक्षणिक सत्र 2007-08 में पी.ई.पी.टी., एम.सी.ए. और एम.ई.टी. तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रवेश के नियम संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अब मैनेजमेंट कोटे की सीटों को केवल एन.आर.आई. उम्मीदवारों से भरा जायेगा। यह संशोधन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 16 अप्रैल 2007 को पारित आदेश के अनुपालन में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के पारित आदेश द्वारा नियम में उल्लेखित निजी क्षेत्र की तकनीकी संस्थाओं में 15 प्रतिशत मैनेजमेंट कोटा अब सिर्फ अप्रवासी भारतीय (एन.आर.आई.) उम्मीदवारों से उपलब्धता के आधार पर भरा जायेगा। शासन ने इस संबंध में व्यावसायिक परीक्षा मंडल को आवश्यक निर्देश दिये हैं।

01 जून 2007

मध्यप्रदेश शासन ने सभी कार्यपालन यंत्रियों को अतिवृष्टि/बाढ़ की स्थिति में सड़क पुलियों के ऊपर पानी के बहाव की संभावना को देखते हुये सुरक्षा के लिये सभी जरूरी आवश्यकतायें पूरी करने के निर्देश दिये हैं। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव श्री पी.डी. मीणा ने इस संबंध में निर्देश जारी कर ऋतु पूर्व सभी पुल-पुलियों का निरीक्षण कर जरूरी सुधार कार्य करने के लिये कहा है। निर्देशों में कहा गया है कि बाढ़ के समय पुल-पुलियों और रपटा या मार्ग क्षतिग्रस्त होने या मार्ग अवरुद्धता की निरंतर जानकारी पुलिस अधीक्षण और जिला दंडाधिकारी को नियमित रूप से दी जाये तथा स्थानीय बस स्टैंड पर भी यह जानकारी सूचना पटल पर आम जनता को मुहैया कराये।

02 जून 2007

मध्यप्रदेश के ग्रामीण इलाकों के पशुपालकों को कम से कम दूरी पर बेहतर पशु चिकित्सा मुहैया कराने के लिये पशु चिकित्सा संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण, उन्नयन, स्थापना और आधुनिकीकरण के कार्यों में वर्ष 2007-08 में 12 करोड़ 08 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे। यह बात भोपाल में विभागीय गतिविधियों की समीक्षा करते हुए पशुपालन मंत्री श्री रमाकांत तिवारी ने कही। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2007-08 में आठ सालों के लंबे अंतराल के बाद ग्यारह नये पशु औषधालय खोले जा रहे हैं जिसके लिये 56 लाख 64 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। आदिवासी उपयोजना के तहत तीन पशु औषधालय खोलने के लिये 25 लाख 40 हजार रुपये रखे गये हैं।

03 जून 2007

मध्यप्रदेश शासन द्वारा निःशक्त व्यक्तियों की शारीरिक विषमताओं को विकसित किये जाने के लिये कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण वगैरह वितरित किये जा रहे हैं। पिछले साल कृत्रिम अंग और उपकरण वितरित किये जाने के लिये 66 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। इस राशि से 2814 हितग्राहियों को फायदा हुआ जबकि इसके पहले वर्ष 2005-06 में 42 लाख 29 हजार रुपये की राशि खर्च की गई थी और 2343 हितग्राहियों को फायदा पहुंचा था। गौरतलब है कि निःशक्तजनों को जो कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण दिये जा रहे हैं उनमें ट्रायसिकल, बैसाखी, व्हीलचेयर, छड़ी, श्रवण यंत्र, कैलीपर्स, कृत्रिम हाथ-पैर शामिल हैं। इसी तरह दृष्टि बाधित अध्ययनरत बालक-बालिकाओं को टेपरिकार्डर निःशुल्क मुहैया कराये जा रहे हैं।

04 जून 2007

मध्यप्रदेश में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने गर्मी के मौसम में ग्रामीण अंचलों में खराब हैण्डपम्प तुरंत सुधारने के निर्देश दिये हैं। इसके लिये सभी जिलों को आवश्यक सामग्री तत्काल उपलब्ध करायी जा रही है। इसी व्यवस्था के कारण इस वित्तीय वर्ष के प्रथम दो महीने में 50 हजार 788 हैण्डपम्प सुधारे गये। इनमें भोपाल परिक्षेत्र में 10 हजार 183, इंदौर परिक्षेत्र में 13 हजार 196, जबलपुर परिक्षेत्र में 10 हजार 867 तथा ग्वालियर परिक्षेत्र में 10 हजार 542 हैण्डपम्प सुधारे गये। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में वर्तमान में विभाग द्वारा 3 लाख 88 हजार 461 हैण्डपम्प स्थापित हैं। इनमें से 3 लाख 43 हजार 438 हैण्डपम्प चालू हालत में हैं। बंद हैण्डपम्पों की संख्या 44 हजार 944 है।

05 जून 2007

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बड़ी कालोनियां विकसित करने में बिल्डर अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करें और इनमें बड़े मकानों के साथ ही निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के लिये भी मकान बनायें। इसी तरह जब बड़ी कॉलोनियों के लिये किसानों की जमीन लें तो उन्हें अपनी योजना स्टेक होल्डर्स बनाकर उन्हें लाभ में भागीदार बनायें। मुख्यमंत्री इंदौर में पी.एच.डी. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा आयोजित रियल स्टेट एण्ड अरबन डेवलपमेंट समिट को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री श्री बाबूलाल गौर, वन एवं परिवहन मंत्री श्री हिम्मत कोठारी तथा लोक निर्माण एवं ऊर्जा मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय विशेष रूप से मौजूद थे।

06 जून 2007

मध्यप्रदेश के प्रमुख सचिव जल संसाधन श्री अरविन्द जोशी ने भोपाल में एक बैठक में सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण की महत्वाकांक्षी परियोजना मध्यप्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट की समीक्षा की। प्रमुख सचिव ने जिन जिलों से सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के लिये तकनीकी प्रस्ताव विश्व बैंक द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार तैयार होकर नहीं आ रहे हैं, उन जिलों के अधिकारियों के प्रति अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि तकनीकी प्रस्तावों की गुणवत्ता के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। साथ ही उन्होंने तकनीकी प्रस्ताव तय की गई समय सीमा में तैयार नहीं करने वाले अधिकारियों को भी कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

07 जून 2007

मध्यप्रदेश सरकार शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में निवेशकों को रियायती दरों पर भूमि और अन्य सुविधाएँ मुहैया करायेगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में सिंगापुर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के सेक्रेट्री जनरल डॉ. आर. थेवेन्द्रन को दी। इस मौके पर सेक्रेट्री जनरल ने कहा कि इंस्टीट्यूट द्वारा नौ देशों में विभिन्न विश्वविद्यालयों के सहयोग से तकनीकी शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य शिक्षा और प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि संस्थान द्वारा मध्यप्रदेश में भोपाल और जबलपुर में प्रशिक्षण संस्थान शुरू करने के लिये परियोजना तैयार की हैं। इस प्रशिक्षण परिसर के शुरू होने से हर साल तकरीबन पांच सौ विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने डॉ. आर. थेवेन्द्रन को आश्वस्त किया कि उन्हें मध्यप्रदेश में काम करने के लिये पूरा सहयोग मिलेगा।

08 जून 2007

मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में दूरी रेशम के विकास के लिये ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार के आदेश के तहत स्वीकृत एस.जी.एस.वाय. विशेष परियोजना के अनुश्रवण तथा मूल्यांकन के लिये राज्य स्तरीय समिति का गठन कर दिया गया है। समिति गठन के तहत इस समिति के अध्यक्ष प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास होंगे तथा समिति के अन्य सदस्यों में प्रमुख सचिव, ग्रामोद्योग के अलावा अन्य सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड बेंगलोर, सचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, सचिव, आदिम जाति कल्याण, कलेक्टर, जिला बैतूल, होशंगाबाद, झाबुआ, रतलाम, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार के प्रतिनिधि आयुक्त, रेशम संचालनालय मध्यप्रदेश तथा फील्ड स्तर की क्रियान्वयन एजेंसी अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे। समिति के सदस्य सचिव प्रबंध संचालक, म.प्र. सिल्क फेडरेशन होंगे।

09 जून 2007

मध्यप्रदेश में पिछले तीन सालों में आम लोगों के हक में परिवहन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कोशिशें की गई हैं। अवैध बसों के संचालन पर लगाम कसने, भ्रष्टाचार के खात्मे के लिये सीमावर्ती परिवहन चौकियों पर इलेक्ट्रॉनिक तौल-कांटों के इंतजाम की शुरुआत के साथ ही जनमानस को आरामदेह बसों में यात्रा की सहूलियत दिलाने के लिये बड़े पैमाने पर अनुबंधित बसों का संचालन राज्य सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। राज्य में लायसेंसिंग प्रणाली के सरलीकरण और ई-सेवा की शुरुआत से आम लोगों को बेहद राहत मिली है। वित्तीय वर्ष 2006-07 में पूर्व वर्ष की तुलना में 13.83 फीसदी का उल्लेखनीय इजाफा हुआ है।

13 जून 2007

मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में एक मई से 31 मई 2007 तक आयोजित जल अभिषेक अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान राज्य के नगरीय निकायों में बड़े पैमाने पर जल संरक्षण कार्य संपन्न हुए। इस रचनात्मक अभियान से शहरी इलाकों में जल संरक्षण और जल संवर्धन के बारे में लोगों में व्यापक जागृति आई है। इस उद्देश्य से 922 दलों का गठन किया गया था। इन दलों ने नगरीय क्षेत्रों में कुल 6089 वार्डों का सघन भ्रमण कर लोगों से जनसंपर्क किया। जल अभिषेक अभियान के दूसरे चरण में इस वर्ष पेयजल की गुणवत्ता पर खासतौर पर ध्यान दिया गया। पेयजल के अपव्यय को रोकने के लिये पाईप लाईनों के 13,323 लीकेज सुधारे गये जिन पर 76 लाख 79 हजार रुपये खर्च हुये।

15 जून 2007

मध्यप्रदेश के अमरकंटक में राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय खोला जायेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस विश्वविद्यालय की स्थापना समेत नागर विमानन नीति, एस.बी.आई. अधिनियम संशोधन अध्यादेश और आतंकियों से निबटने की कार्यप्रणाली समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिये गये। देश के आदिवासियों को उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधाएं मुहैया कराने के लिये अमरकंटक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित केबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई।

16 जून 2007

प्रदेश में विगत साढ़े तीन वर्षों में स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर सुधार हुआ है। प्रदेश में जहां सभी स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण कार्य को स्वीकृति दी गई है वहीं मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया गया है। यह जानकारी किसान कल्याण मंत्री श्री चंद्रभान सिंह ने छिंदवाड़ा में दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले 2 करोड़ व्यक्तियों को दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना के अंतर्गत निःशुल्क बेहतर

स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के साथ ही प्रतिवर्ष 20-20 हजार रुपये की दवाईयां भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री चंद्रभान सिंह ने छिंदवाड़ा विकासखंड के ग्राम रोहनाकला और मोहखेड़ विकासखंड के ग्राम शिकारपुर में नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। उन्होंने रोहनाकला में लोक निर्माण विभाग के मद से लगभग 10.13 लाख रुपये लागत से गुरैया से रोहना और लगभग 13.65 लाख रुपये लागत से रोहना से मुलताई मार्ग तक सड़क नवीनीकरण और डामरीकरण का भूमिपूजन भी किया। उन्होंने इस अवसर पर बताया कि प्रदेश में विगत साढ़े तीन वर्षों में 25 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो चुका है, जिससे प्रदेश में कई उद्योगपति पूंजी निवेश के लिए आकर्षित हुए हैं।

23 जून 2007

मध्यप्रदेश शासन द्वारा सागर जिले की पांच लघु सिंचाई योजनाओं के लिये 26 करोड़ 87 लाख 29 हजार रुपये की मंजूरी दी गई है। इन योजनाओं से 2862 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। जल संसाधन विभाग द्वारा जिले के तीन विकासखंडों देवरी, केसली और राहतगढ़ की एक-एक तालाब योजना और दो विकासखंडों जैसीनगर और रहली की एक-एक वियर योजना के लिये प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। देवरी विकासखंड की सतधारा तालाब योजना के लिये 20 करोड़ 91 लाख 21 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी है। इससे 2112 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी।

24 जून 2007

मध्यप्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आर्थिक स्थिति का कोई बंधन नहीं है। कोई भी व्यक्ति विवाह समारोह में अपनी कन्या का विवाह करा सकता है। यह बात प्रदेश के कृषक कल्याण मंत्री चौधरी चन्द्रभान सिंह ने छिंदवाड़ा में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे प्रदेश की बेटियों खासकर गरीब बेटियों के विवाह में आर्थिक समस्या को देखते हुये सरकार की ओर से उनके विवाह का फैसला लिया है तथा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत प्रदेश सरकार सभी गरीब बेटियों के विवाह के लिये वचनबद्ध है। श्री सिंह ने कहा कि विवाह समारोह के लिये आर्थिक स्थिति का कोई बंधन नहीं है तथा कोई भी व्यक्ति समारोह में अपनी कन्या का विवाह करा सकता है।

25 जून 2007

मध्यप्रदेश सरकार ने अतिक्रमणमुक्त प्रदेश का लक्ष्य रखा है। भविष्य में अतिक्रमण पाये जाने पर सरपंच, पंचायत सचिव और पटवारी को जिम्मेदार माना जायेगा। यह बात राजस्व, पुनर्वास, धर्मस्व एवं धार्मिक न्यास मंत्री श्री कमल पटेल ने भोपाल में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समस्त शासकीय स्थलों का सीमांकन कर उनके आसपास हुये अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी। श्री पटेल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा वातावरण बनायें जिससे ग्रामीणों को खुद यह आभास हो कि अतिक्रमण हटाने से उन्हें ही फायदा होगा। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों, किसानों तथा गरीबों को राजस्व विभाग से होने वाली परेशानी को दूर करने के लिये पूरे प्रदेश में विशेष राजस्व अभियान चलाया जा रहा है।

27 जून 2007

मध्यप्रदेश शासन ने राज्य बीमारी सहायता निधि के नियमों में कतिपय संशोधन किये हैं। नियमों में संशोधन संबंधी अधिसूचना जारी की गई है। भोपाल से मिली जानकारी के मुताबिक पहले संशोधन में प्रबंध समिति द्वारा सहायता राशि स्वीकृत किये जाने के बाद मरीज के इलाज के लिये प्राक्कलन प्राप्त होने पर जिला बीमारी सहायता निधि/राज्य बीमारी सहायता निधि से आवश्यक राशि जारी की जायेगी, जोड़ा गया है। एक अन्य संशोधन में मरीज को परिवहन के लिये दो हजार रुपये की राशि देने का प्रावधान किया गया है। गरीबी की रेखा के नीचे जीवन गुजारने वाले परिवार के रोगियों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा कलेक्टर की अनुशंसा पर जिला बीमारी सहायता निधि से दो हजार रुपये रोगी के नाम परिवहन के लिये दिये जायेंगे। शेष राशि अस्पताल के नाम जांच के लिये चैक के द्वारा दी जायेगी।

28 जून 2007

मध्यप्रदेश के दस नगरों के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये प्रथम चरण में चयन किया गया है। इनमें कटनी, दमोह, विदिशा, देपालपुर, मैहर, चित्रकूट, छतरपुर, होशंगाबाद, सीहोर और रायसेन शामिल हैं। इन नगरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति जनजागरूकता के लिये प्रचार-प्रसार का अभियान चलाने का फैसला भी लिया गया है। चुने गये नगरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्ययोजना बनाई जा रही है। इस मकसद से भोपाल और जबलपुर शहरों में हो रहे तकनीकी कार्यों और जनजागरूकता के लिये प्रचार-प्रसार की योजनाओं के आधार पर अभियान का क्रियान्वयन किया जायेगा।

29 जून 2007

मध्यप्रदेश शासन द्वारा राज्य को अन्त्योदय अन्न योजना के लिये दिये गये राशन कार्डों के लक्ष्य के अनुरूप मई 2007 से मार्च 2008 तक के लिये खाद्यान्न का मासिक आवंटन मुहैया कराया गया है। आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ने समस्त कलेक्टरों को जिलेवार मासिक आवंटन में संशोधन कर जिलों को आवंटित लक्ष्य के अनुरूप अन्त्योदय खाद्यान्न का संशोधित आवंटन जारी कर दिया है। भोपाल में आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिये हैं कि जिलों में नवीन अन्त्योदय कार्ड जिलों को आवंटित लक्ष्य के अनुरूप ही बनाये जायें। निर्देश के मुताबिक लक्ष्य से ज्यादा निर्मित हुए कार्डों के लिये खाद्यान्न का आवंटन उपलब्ध कराया जाना मुमकिन नहीं होगा।

30 जून 2007

मध्यप्रदेश में सुरक्षित मातृत्व और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिये क्रियान्वित की जा रही जननी सुरक्षा योजना के बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। राज्य के तीन जिलों के ब्लॉक ने तो संस्थागत प्रसव के मामले में शत-प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की है। ये ब्लॉक हैं, गुना जिले का आरोन, शहडोल जिले का ब्यौहारी और खरगोन जिले का ठीकरी। जननी सुरक्षा योजना के शुरू होने से लेकर अब तक लगभग चार लाख महिलाओं को फायदा हो चुका है। जननी सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन में पिछले साल प्रदेश में पांच जिलों ने शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल की है। ये जिले हैं, देवास, सीहोर, ग्वालियर, खंडवा और गुना। शासन ने प्रदेश के सभी जिलों को कम से कम 60 प्रतिशत संस्थागत प्रसवों का लक्ष्य निर्धारित किया है। कार्यकर्ता को हितग्राही के साथ अस्पताल पहुंचने के लिये प्रेरित करने और हितग्राही के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश जिलों को दिये गये हैं।

02 जुलाई 2007

मध्यप्रदेश में मानसून की आमद होते ही प्रदेश में खरीफ के फसल की बोनी शुरू हो गई है। अब तक प्राप्त खबरों के मुताबिक प्रदेश में 84.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। प्रदेश में अब तक 22 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की

बोनी की गई है। प्रदेश में अब तक सोयाबीन की बोनी दस लाख हैक्टेयर में की गई है। अब तक एक लाख हैक्टेयर क्षेत्र में धान बोई गई है। धान की बोनी प्रमुख धान उत्पादक जिलों मंडला, डिंडौरी, बालाघाट में की गई है। इसी प्रकार से कपास की बोनी 4 लाख हैक्टेयर में ज्वार एक लाख हैक्टेयर में बोई गई है। इसी तरह से प्रदेश में तुअर दो हजार उड़द और मूंग एक-एक हजार हैक्टेयर क्षेत्र में बोई गई हैं।

03 जुलाई 2007

मध्यप्रदेश के पांच जिलों पन्ना, भिंड, जबलपुर, उमरिया और छतरपुर में 2006-07 में प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.सी.एच.) और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) की राशि का बेहतर इस्तेमाल किया गया। आर.सी.एच. और एन.आर.एच.एम. की वार्षिक कार्ययोजना के तहत पन्ना ने पिछले साल कुल आवंटित राशि में से 76.70 प्रतिशत, भिंड ने 62.95 प्रतिशत, जबलपुर ने 62.23 प्रतिशत, उमरिया ने 60.84 प्रतिशत और छतरपुर ने 59.44 प्रतिशत राशि का इस्तेमाल किया गया है।

05 जुलाई 2007

मध्यप्रदेश में समग्र स्वच्छता अभियान के तहत पिछले तीन सालों में 6 लाख 75 हजार 436 शौचालयों का निर्माण कराया गया है। इनमें 6 लाख 40 हजार 826 शौचालयों का निर्माण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिये कराया गया है। अभियान के तहत पारिवारिक स्वच्छ शौचालयों के निर्माण के लिये तकनीकी और वित्तीय सहयोग और शालाओं में स्वच्छता संबंधी सुविधाओं में इजाफे की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि प्रदेश में हितग्राहियों और शासन के सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मकसद ग्रामीण जनजीवन के स्तर में गुणवत्ता के आधार पर सुधार लाना है।

11 जुलाई 2007

मध्यप्रदेश शासन ने शहरी गरीबी और जीविका प्रकोष्ठ की स्थापना के संबंध में राज्यस्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन और विकास होंगे। शासन द्वारा भारत सरकार के आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत यू.एन.डी.बी. की सहायताकृत परियोजना 'नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर अर्बन पुअर' के तहत इस समिति का गठन किया गया है। शहरी गरीबी और जीविका प्रकोष्ठ की स्थापना के संबंध में गठित समिति में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा, प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास तथा सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को सदस्य बनाया गया है। आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास समिति के सदस्य सचिव बनाये गये हैं। यह समिति जो कार्य संपादित करेगी उनमें परियोजना से संबंधित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा मॉनीटरिंग, विभाग में गरीबों से संबंधित योजना पर सलाह देना, प्रकोष्ठ के उद्देश्यों के पालन के तहत प्रगति की समीक्षा, शहरी गरीबी उपशमन में रणनीति तैयार करने में मार्गदर्शन और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन तथा आई.एच.एस.डी.पी. योजना का अन्य विभागों की अन्य योजना से सामंजस्य स्थापित करना शामिल है।

15 जुलाई 2007

मध्यप्रदेश शासन का एक ही लक्ष्य है प्रदेश का विकास और जनकल्याण। यह बात इंदौर में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जनदर्शन के दौरान अधिकारियों को संबोधित करते हुये कही। उन्होंने अधिकारियों से अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल प्रदेश के विकास में करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दिया जाये।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये कि ऐसे पारदर्शी इंतजाम किये जायें, जिसमें लोगों को भटकना न पड़े। श्री चौहान ने कहा कि ऐसी कोशिश की जाये कि जाति प्रमाण-पत्र, नामांतरण और सीमांकन के मामले समय पर निबटाये जायें। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि रबी मौसम में किसानों को बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।

16 जुलाई 2007

मध्यप्रदेश के ग्यारह जिलों में स्वीकृत किये गये आई.सी.डी.एस. सेल के कार्यालयों के लिये कुल 66 नये पद इजाद करने की स्वीकृति राज्य शासन द्वारा दी गई है। यह निर्णय भोपाल में राज्य मंत्रिपरिषद् की पिछली बैठक में प्रदेश के ग्यारह जिलों में आई.सी.डी.एस. सेल खोलने के तहत लिया गया था। इन ग्यारह जिलों के लिये गठित किये जाने वाले आई.सी.डी.एस. सेल के कार्यालय में कुल छह शासकीय कर्मचारियों का अमला रहेगा। इस प्रकार छह स्तरों के 11-11 नये पद मंजूर किये गये हैं।

17 जुलाई 2007

मध्यप्रदेश शासन ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल की शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिये एक करोड़ 25 लाख रुपये की राशि मंजूर की है। भोपाल से प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह राशि तकनीकी एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिये आयोजित परीक्षा में शामिल होने वाले आदिवासी छात्र-छात्राओं को परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिये जारी की गई है। गौरतलब है कि शासन ने 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2007-2012 में एक करोड़ 25 लाख रुपये और वर्ष 2007-08 में 25 लाख रुपये खर्च करने की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

19 जुलाई 2007

मध्यप्रदेश शासन द्वारा मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में स्थित इन्द्रगढ़ पहाड़ी के शैलाश्रय को राज्य संरक्षित स्मारक के तौर पर घोषित करने के लिये अधिसूचना जारी कर दी गई है। भोपाल से मिली जानकारी के मुताबिक इन्द्रगढ़ पहाड़ी के शैलाश्रय वनभूमि कम्पार्टमेंट नंबर 1036 में स्थित है। इन्द्रगढ़ पहाड़ी के शैलाश्रय को क्षतिग्रस्त होने, विकृत किये जाने, तितर-बितर किये जाने आदि से बचाने के मकसद से इसे संरक्षित करना जरूरी है। गौरतलब है कि म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से दो महीने की कालावधि खत्म होने के पूर्व आपत्ति किये जाने पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जा सकेगा।

20 जुलाई 2007

मध्यप्रदेश में कृषि क्षेत्र के तहत किसानों को उनकी मेहनत की वाजिब कीमत देने के मकसद से कृषि उपज आधारित उद्योगों के लिये उद्योग नीति के तहत नवीन नीति करने के लिये राज्य शासन द्वारा एक समिति गठित की गई है। इस समिति के अध्यक्ष प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास तथा अन्य सदस्यों में प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर, सचिव वित्त, पदेन सचिव उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण और पदेन सचिव वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार होंगे। गौरतलब है कि यह समिति कृषि क्षेत्र के तहत मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के मकसद से गठित की गई है। यह एक महीने में खाद्य प्रसंस्करण और कृषि उपज आधारित उद्योगों के लिये नीति तैयार कर पेश करेगी।

मध्यप्रदेश शासन ने प्रदेश के निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था में प्रवेश और फीस विनियामक समिति के अध्यक्ष के पद पर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के पूर्व कुलपति श्री पुरुषोत्तम लाल चतुर्वेदी को नियुक्त किया है। श्री चतुर्वेदी का कार्यकाल 24 मई 2010 तक रहेगा। गौरतलब है कि पूर्व में गठित समिति के अध्यक्ष प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा थे जिनके स्थान पर यह नियुक्ति की गई है।

21 जुलाई 2007

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में इस्कॉन द्वारा संचालित मध्याह्न भोजन की नागझिरी स्थित पाकशाला का अवलोकन किया। मध्याह्न भोजन के प्रभारी श्री संदीप गुप्ता ने कहा कि उज्जैन शहर के 143 स्कूलों के लगभग 21 हजार विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन करवाया जावेगा। उन्होंने कहा कि अभी वर्तमान में शहर के 60 विद्यालयों में 7 हजार बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है। शेष 83 विद्यालयों में भी 30 जुलाई तक मध्याह्न भोजन दिया जाना शुरू कर दिया जायेगा। गौरतलब है कि अत्याधुनिक मशीनों द्वारा एक घंटे में मशीन से दस हजार रोटियां तथा एक घंटे में ही दूसरी मशीन की मदद से दस हजार पूड़ियां बनाई जाती हैं। इसके अलावा तीन स्टीम जैकेट में मध्याह्न भोजन की सब्जी बनाई जाती है। बीस मिनट में तीन सौ किलो सब्जी तैयार की जाती है।

26 जुलाई 2007

मध्यप्रदेश शासन ने पर्यटन से संबंधित नीतिगत फैसले लेने और पर्यटन विकास में विभागों की समन्वित भागीदारी सुनिश्चित करने के मकसद से मंत्रिपरिषद् समिति का पुनर्गठन किया है। भोपाल में हुये इस मंत्रिपरिषद् समिति के पुनर्गठन के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान अध्यक्ष होंगे। इस समिति के सदस्यों के रूप में वित्त मंत्री श्री राघवजी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री जयंत मलैया, लोक निर्माण मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री श्री अनूप मिश्रा, आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री विजय शाह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रुस्तम सिंह, राजस्व मंत्री श्री कमल पटेल और जनसंपर्क एवं गृह राज्यमंत्री श्री नागेन्द्र सिंह को मनोनीत किया गया है। तीन महीने में एक बार आयोजित होने वाली इस बैठक के सचिव, पर्यटन होंगे जो इस मंत्रिपरिषद् समिति के सचिव होंगे।

28 जुलाई 2007

मध्यप्रदेश में कृषि यंत्रों में लकड़ी के इस्तेमाल की जगह लोहे के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। भोपाल से मिली जानकारी के मुताबिक किसानों को ऐसे कृषि यंत्र बांटने में मध्यप्रदेश देश में पहले स्थान पर है। अभी तक कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पिछले तीन सालों में दो लाख 25 हजार से ज्यादा कृषि यंत्र किसानों को प्रदाय किये गये हैं इसमें ट्रेक्टर भी शामिल है। गौरतलब है कि कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि यंत्रों का निर्माण आधुनिक और वैज्ञानिक विधि से करने पर खासतौर पर ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के कारीगरों और मिस्त्रियों के कौशल में इजाफे के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

29 जुलाई 2007

मध्यप्रदेश शासन द्वारा खरीफ 2007 मौसम की मुख्य फसलों सोयाबीन, तुअर, धान, मक्का और बाजरा फसल के लिये फसल बीमा की इकाई तहसील स्तर से घटाकर अब पटवारी हल्का स्तर कर दी गई है। योजना के जरिये प्राकृतिक आपदाओं और रोगों के कारण अधिसूचित फसलों के नष्ट होने पर किसानों को वित्तीय मदद दी जाती है। गौरतलब है

कि मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना वर्ष 1999-2000 से शुरू की गई है। इस योजना की मुख्य क्रियान्वयन एजेंसी एग्रीकल्चर कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड है तथा नोडल विभाग किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग है।

31 जुलाई 2007

मध्यप्रदेश में खेत तालाब योजना के तहत पिछले साल बनाये गये तालाबों में बारिश का पानी भरना शुरू हो गया है। अगर यह तालाब बारिश के पानी से भर जाते हैं तो जल स्तर में इजाफा होगा। खेत तालाब बन जाने से भू-जल स्तर में इजाफा तो होगा ही साथ ही फसलों को जीवनरक्षक सिंचाई क्षमता मुहैया होगी। योजना के तहत खेत तालाब बनाने की योजना में इस साल 21 करोड़ 64 लाख रुपये से ज्यादा का प्रावधान किया गया है जो कि पिछले साल से ज्यादा है। गौरतलब है कि योजना के तहत बनाये गये एक खेत तालाब से आधा से डेढ़ हैक्टेयर क्षेत्र तक सिंचाई की जा सकती है।

01 अगस्त 2007

मध्यप्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद् भोपाल ने अपनी वेबसाइट www.mpbiotech.org लांच की है। यह परिषद् प्रदेश के जैव विविधता और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के तहत कार्यरत है। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा बॉयोटेक्नालॉजी के विकास और अनुसंधान के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों और परिषद् की गतिविधियों की जानकारी इस वेबसाइट पर मिल सकती है।

02 अगस्त 2007

मध्यप्रदेश भारत के बड़े राज्यों में से एक है जहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी का होना बेहद जरूरी है। मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी के रूप में उन्नत किये जाने की पात्रता रखता है क्योंकि इसकी वजह कॉलेज की मान्यता पिछले पचास सालों से राज्य के उच्च स्तरीय संस्था के रूप में है। यह अनुरोध किया है प्रदेश के राज्यपाल डॉ. बलराम जाखड़ ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह से। गौरतलब है कि पिछले दिनों मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी के छात्रों और शैक्षणिक संकाय से संबंधित दलों ने राज्यपाल से मिलकर महाविद्यालय को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी के रूप में उन्नत किये जाने का आग्रह किया था।

03 अगस्त 2007

मध्यप्रदेश शासन ने प्रमुख सचिव राजस्व की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। इसके तहत यह समिति नजूल नवीनीकरण और पट्टों की शर्तों का सरलीकरण, रांझी (जबलपुर) के नजूल भूमि व्यवस्थापन, अर्बन एंड सीलिंग एक्ट की विसंगतियों को दूर करने तथा वर्ष 2002 में निर्धारित नजूल पट्टों के नवीनीकरण और प्रब्याजी आरोपण को व्यवहारिक बनाने के सुझाव और परीक्षण कर राज्य शासन को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। प्रमुख सचिव वित्त के अलावा इंदौर, ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर के आयुक्त सदस्य होंगे। एक महीने में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाली इस समिति के अपर सचिव राजस्व श्री प्रदीप खरे को संयोजक बनाया गया है।

08 अगस्त 2007

मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, विज्ञान भारती एवं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के तत्वावधान में भारतीय विज्ञान सम्मेलन का आयोजन आगामी 23 से 25 नवंबर 2007 को भोपाल में किया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, बैंगलूर के अध्यक्ष डॉ. जी. माधवन नायर इस आयोजन सम्मेलन की आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं। इस सम्मेलन में देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों एवं तकनीकविदों, शिक्षाविदों, नीति निर्धारकों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों के अलावा विज्ञान में रुचि रखने वालों को आमंत्रित किया गया है।

21 अगस्त 2007

मध्यप्रदेश के खाद्य नियंत्रक और औषधि प्रशासन ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे केवल पैकिंग में उपलब्ध पिसे मसालों एवं अन्य खाद्य पदार्थों को ही प्राथमिकता दें और बाहर से खुले पिसे मसाले खरीदने से बचें। अप्राकृतिक रूप से भड़कीले रंगों के मसाले, मिठाइयां, शर्बत, आइसक्रीम में मिलावट की संभावना अधिक होती है। एगमार्क द्वारा प्रमाणित मसाले, घी, शहद का उपयोग करें। खाद्य सामग्री की पैकिंग पर निर्माता, वास्तविक वजन, मूल्य, बैच नंबर एवं पैकिंग का दिनांक, माह एवं वर्ष अंकित होना चाहिए।

23 अगस्त 2007

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की स्थिति की समीक्षा के लिए मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा गठित स्टेंडिंग कमेटी के अध्यक्ष जफर अली नकवी और सदस्यों से भेंट की। श्री नकवी ने मुख्यमंत्री को प्रदेश में अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक संस्थाओं की समस्याओं से अवगत कराया। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में शीघ्र ही उर्दू के जानकार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।

25 अगस्त 2007

मध्यप्रदेश राज्य मंत्रिपरिषद् में नवनियुक्त 6 मंत्रियों को वल्लभ भवन स्थित राज्य मंत्रालय में कक्ष आवंटित कर दिए गए हैं। मंत्रिपरिषद् में शामिल केबिनेट मंत्री श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ को तीसरी मंजिल पर कक्ष क्रमांक 327, श्री गौरीशंकर शेजवार को पांचवीं मंजिल पर कक्ष क्रमांक 545 एवं श्री अखण्ड प्रताप सिंह को पांचवीं मंजिल पर कक्ष क्रमांक 537 आवंटित किए गए हैं। वहीं राज्यमंत्री श्री करण सिंह वर्मा को पांचवीं मंजिल पर कक्ष क्रमांक 535, सुश्री रंजना बघेल को तीसरी मंजिल पर कक्ष क्रमांक 326 एवं श्री हरेन्द्रजीत सिंह 'बब्बू' को कक्ष क्रमांक 112 आवंटित किया गया है।

26 अगस्त 2007

मध्यप्रदेश शासन ने श्रीमती अमिता चपरा को म.प्र. राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्रीमती कृष्णकांता तोमर, श्रीमती अंजू माखीजा, सुश्री राजो मालवीय, सुश्री सरिता देशपांडे और सुश्री सुषमा आर्य को आयोग का सदस्य बनाया गया है।

27 अगस्त 2007

मध्यप्रदेश शासन ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्यमों (लायसेंस धारियों) के संबंध में गठित समिति में वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के प्रमुख सचिव को अध्यक्ष नामांकित किया है। यह समिति ऐसे उद्यमों को राइट ऑफ वे की स्वीकृतियां एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत एक ही स्थान पर उपलब्ध हों, इसलिए गठित की गई है।

28 अगस्त 2007

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नरसिंहपुर जिले के मुराच गांव में फायरिंग में मृत किशोर के परिजनों को दो लाख रुपये की सहायता मंजूर की है। मृतक के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री ने जिला तथा पुलिस प्रशासन को मामले की जांच के आदेश दिये हैं। उल्लेखनीय है कि 27 अगस्त को अवैध लकड़ी जब्त करने के लिये गये वन विभाग के दल पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। वन विभाग के दल के साथ गए राज्य सशस्त्र बल के सिपाहियों ने अपने बचाव में हवाई फायर किए जिसमें किशोर की मौत हो गई।

30 अगस्त 2007

मध्यप्रदेश शासन ने ऐच्छिक संस्थाओं को शैक्षणिक और अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिये अनुदान के लिये 22 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि का प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। यह राशि ऐच्छिक संस्थाओं की ग्रेडिंग करने की शर्त पर मंजूर की गई है। तीन वर्ष के परिणाम संतोषजनक न होने पर संस्थाओं का अनुदान बंद करने का प्रस्ताव शासन के समक्ष रखा जाएगा। शासन ने ऐच्छिक संस्थाओं को अनुदान के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2007-2012 में 22 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि मंजूर की है तथा वर्ष 2007-08 के लिए चार करोड़ 50 लाख रुपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

31 अगस्त 2007

म.प्र. की सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री श्रीमती रंजना बघेल ने भोपाल स्थित मंत्रालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। श्रीमती बघेल ने निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों की कम उपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए सभी को समय पर उपस्थित होने के निर्देश दिए। राज्यमंत्री ने मंत्रालय में साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया।

01 सितम्बर 2007

मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों के उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडलों के मध्य आवंटन की कार्रवाई पुनः प्रारंभ हो गई है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में इस प्रक्रिया पर विराम लगा था। भारत शासन द्वारा जारी निर्देशों एवं गठित राज्य सलाहकार समिति विद्युत मंडल में दोनों राज्यों के बीच हुई बैठक में सहमति के आधार पर आवंटन की कार्रवाई पुनः प्रारंभ हुई है। नवीन प्रक्रिया में आवंटन का प्रमुख आधार राज्य आवंटन हेतु प्रस्तुत विकल्प होगा। इस प्रक्रिया में भारत शासन के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों का आवंटन जो 31.10.2002 तक सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हीं मंडलों में किया जा रहा है, जिनमें वे सेवानिवृत्ति के समय कार्यरत थे। अधिकारी और कर्मचारी प्रस्तावित आवंटन के संबंध में एक माह की समयावधि में राज्य समिति के विचारार्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

03 सितम्बर 2007

मध्यप्रदेश शासन ने झाबुआ जिले की सात लघु सिंचाई योजनाओं के लिये 7 करोड़ 64 लाख 70 हजार रुपये की राशि मंजूर की है। इन योजनाओं से 621.40 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। जल संसाधन विभाग द्वारा जिले के थांदला विकासखंड की खटावाला तालाब योजना के लिये एक करोड़ 64 लाख 62 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। सोण्डवा विकासखंड की उमरठ तालाब क्रमांक-2 योजना के लिये 63 लाख 69 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा जिले के पेटलावद विकासखंड की पांच, बेकल्दा, उण्डीखाली, बिजौरी, मथुरिया और पटेल का नाका तालाब योजना के लिये प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

05 सितम्बर 2007

मध्यप्रदेश शासन ने गृह विभाग के अधीन गुप्तचर एवं सुरक्षा एजेंसियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के दायरे से बाहर रखा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बारे में मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी है। सूचना का अधिकार के प्रावधानों से मुक्त रखी गई गुप्तचर एवं सुरक्षा एजेंसियों में पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा तथा गृह विभाग की शाखा 'सी' शामिल है। सीआईडी (केवल गुप्तचर एवं सुरक्षा से संबंधित विषयों के लिये) और विशेष सशस्त्र बल (एसएएफ) को भी इस अधिनियम के प्रावधानों से मुक्त रखा गया है।

10 सितम्बर 2007

मध्यप्रदेश के राजस्व मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि राज्य तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक विकास के लाभ को पहुंचाना हमारी सरकार का संकल्प है। श्री पटेल ने टीकमगढ़ जिले के आलमपुरा गांव में हाईस्कूल भवन के उन्नयन और नवीन निर्माण कार्य का लोकार्पण भी किया, साथ ही उन्होंने आलमपुरा-बन्ने बुजुर्ग तक के 7.40 कि.मी. लंबे ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य का भूमिपूजन भी किया।

11 सितम्बर 2007

मध्यप्रदेश शासन ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री नरेन्द्र गणेश करमबेल को सरदार परियोजना विस्थापितों के लिये कार्यरत शिकायत निवारण प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। सरदार सरोवर शिकायत निवारण प्राधिकरण परियोजना से विस्थापित होकर मध्यप्रदेश में पुनर्वासित हुए और होने वाले परिवारों की शिकायतों के निराकरण का कार्य करता है। शिकायत निवारण प्राधिकरण अब तक विस्थापितों की 8000 से अधिक शिकायत आवेदनों का निराकरण कर चुका है।

12 सितम्बर 2007

मध्यप्रदेश में पिछले एक साल में 17 प्रतिशत टीकाकरण बढ़ा है। भारत शासन द्वारा यूनिवर्सल कव्हरेज इव्युलेशन (यू.सी.ई.) के अंतर्गत दिसंबर 2006 की स्थिति में यह तथ्य सामने आया है। सर्वे में पाया कि राज्य में दिसंबर 2005 में जहां सम्पूर्ण टीकाकरण का प्रतिशत 38.9 था, वहीं दिसंबर 2006 में यह 55.8 प्रतिशत हो गया। टीकाकरण सहित अन्य स्वास्थ्य सूचकांकों में हो रहे उल्लेखनीय सुधार व प्रगति का मुख्य कारण राज्य में आर.सी.एच. और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का सफल क्रियान्वयन है। राज्य में दिसंबर 2007 की स्थिति में 12 से 23 माह के शिशुओं में सम्पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य 60 प्रतिशत रखा गया है।

13 सितम्बर 2007

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के प्रति सदैव कृतज्ञ रहने और उन्हें उचित सम्मान देने की आवश्यकता है। भोपाल के शासकीय कमला नेहरू हायर सेकंडरी विद्यालय में शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए अपने गुरू श्री रतनचंद्र जैन के मार्गदर्शन को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन की दिशा प्रायमरी शिक्षा स्तर से ही तय हो जाती है। इस अवसर पर श्री चौहान ने विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं को उनके उत्कृष्ट शिक्षण के लिए सम्मानित भी किया।

16 सितम्बर 2007

मध्यप्रदेश के आदिवासी विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस साल प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है। राज्य शासन ने आईआईटी, एआईईईई तथा सीपीएमटी एवं पीएमटी की परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक इस वर्ग के विद्यार्थियों को संभाग स्तर के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं में कोचिंग कराने की योजना स्वीकृति की है। ऐसे उम्मीदवार जिनके परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम हो, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इच्छुक विद्यार्थियों को अपने जाति एवं आय प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र के साथ अपना आवेदन पत्र अपने जिले के जिला संयोजक/सहायक आयुक्त/संभागीय उपायुक्त को प्रस्तुत करना होगा।

19 सितम्बर 2007

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के औद्योगिक विकास की स्थिति की नियमित समीक्षा की गई है। इसका उद्देश्य उद्योगों की मुश्किलों को दूर कर प्रदेश को तेजी से उन्नत राज्य का दर्जा दिलाना है। फूड पार्क की स्थापना और ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में शीघ्र कदम उठाए जायेंगे। नीदरलैंड के प्रमुख उद्योगपति हैंक शिफर्स एवं मेसर्स फेड टेक के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने ये बात कही। श्री शिफर्स ने बताया कि उनकी कंपनी डच एवं भारतीय व्यापार को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रही है। कंपनी मध्यप्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण एवं रिनोवेबल ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की इच्छुक है। मुख्यमंत्री ने श्री शिफर्स को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

21 सितम्बर 2007

मध्यप्रदेश के 14 कपास उत्पादक जिलों में केन्द्र और राज्य शासन के सहयोग से कपास प्रौद्योगिकी मिशन का मिनी मिशन-2 कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम केन्द्र और राज्य शासन के सहयोग से चलाया जा रहा है। योजना के घटकों में केन्द्र और राज्य की 75-25 की भागीदारी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कपास उत्पादक कृषकों को उत्तम गुणवत्ता वाले कपास के अधिक उत्पादन के लिये प्रेरित करना है। इस योजना के अंतर्गत प्रमाणित बीज उपचार हस्तचलित एवं शक्ति चलित स्प्रेयर डीलिटिंग प्लांट की स्थापना बायो एजेंट लेब की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, बायो एजेन्ट, बायो पेस्टीसाईड्स वितरण, फेरोमेन ट्रेप्स, कृषि यंत्रों का अग्र पंक्ति प्रदर्शन, स्प्रिंकलर सेट तथा टपक सिंचाई आदि घटक सम्मिलित किये गये हैं।

22 सितम्बर 2007

मध्यप्रदेश के 11 नगरों की प्रमुख सात नदियों के संरक्षण की 22 योजनाओं के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। ये योजनाएं गंगा परियोजना के अनुरूप अन्य मुख्य नदियों के प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थीं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा देश की प्रमुख नदियों के प्रदूषण निवारण की योजना बनाई गई थी। इसके अंतर्गत प्रदेश के 11 नगर इंदौर, बुरहानपुर, उज्जैन, नागदा, भोपाल, मंडीदीप, विदिशा, जबलपुर, सिवनी, छपारा एवं केवलारी शामिल किए गये थे। इन नगरों में स्थित खान, ताप्ती, क्षिप्रा, चम्बल, बेतवा, वैनगंगा एवं नर्मदा नदी के प्रदूषण निवारण के लिए 26 योजनायें बनाई गई थीं।

24 सितम्बर 2007

मध्यप्रदेश के किसानों को मानक स्तर का उन्नत बीज उपलब्ध कराने के लिये प्रदेश में चार बीज गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें स्थापित हैं। इनमें से एक प्रयोगशाला विभागीय, दो बीज प्रमाणीकरण संस्था तथा एक तिलहन संघ के अधीन है। प्रयोगशालाओं में जनवरी, 2007 तक 3314 बीज नमूनों का परीक्षण किया गया एवं दो हजार 471 नमूने मानक स्तर के पाए गए। जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर तथा भोपाल में स्थापित राज्य की चार उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाओं में जनवरी तक 5 हजार 367 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिसमें से 4 हजार 224 नमूने मानक स्तर के पाए गए। वहीं जबलपुर स्थित प्रदेश की एकमात्र कीटनाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला में जनवरी, 2007 तक 996 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें से 922 नमूने मानक स्तर के पाए गए।

26 सितम्बर 2007

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत में यूनीसेफ के प्रतिनिधि श्री सेसिलियो एडोरना से भेंट की। श्री एडोरना हाल ही में न्यूयार्क स्थानांतरित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने एडोरना के कार्यकाल में बाल कल्याण में प्राप्त उपलब्धियों के लिये उन्हें बधाई दी। श्री एडोरना ने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बच्चों में कुपोषण समाप्ति के लिये प्रारंभ की जा रही शक्तिमान परियोजना की सराहना की।

29 सितम्बर 2007

प्रदेश की कृषि भूमि का 30 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है, जिसकी वृद्धि के लिये निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में गन्ना नगद फसल में मुख्य है। पिछले वर्ष राज्य के लगभग 55 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में गन्ना उत्पादन हुआ था जो वर्ष 2006-07 में बढ़कर लगभग 76 हजार हैक्टेयर हो गया है। आगामी वर्षों में इसके 80-85 हजार हैक्टेयर क्षेत्र हो जाने की संभावना है। वर्ष 2006-07 में गन्ने का उत्पादन, शक्कर मिलों में पिराई क्षमता से अधिक होने, गन्ने के भाव कम होने के फलस्वरूप कृषकों को गन्ना अन्यत्र जिले या राज्य से बाहर ले जाने के लिए विशेष परिस्थिति में 'केवल वर्ष 2006-07 के पिराई सत्र के लिये' गन्ना उत्पादक कृषकों को प्रोत्साहन देने के लिये गन्ना परिवहन अनुदान 25 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

30 सितम्बर 2007

प्रदेश के श्रममंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना में पात्र खेतिहर श्रमिकों को हिताधिकारी बनाने के निर्देश दिये हैं। असंगठित क्षेत्र के भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों के लिये बेहतर कार्यदशाएं तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने के लिये 11 अक्टूबर से श्रमिकों का पंजीयन किया जायेगा। श्री देवड़ा ने इसके लिये श्रमिक संगठनों से भी सहयोग लेने के निर्देश दिये हैं। ग्रामीण महिला व पुरुष जिनके स्वयं के एवं उनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर खेती की भूमि नहीं हो, भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों में शामिल किये जायेंगे। मुख्यतः खेती, उद्यानिकी, वनरोपण तथा वनोपज आदि काम करने वाले लोगों को इस योजना में हिताधिकारी बनाया जायेगा। इसके लिये श्रमिक को एक वर्ष में कम से कम 90 दिन कार्य करना अनिवार्य है। योजना के अंतर्गत श्रमिकों का पंजीयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जायेगा। यह पंजीयन तीन वर्ष तक वैध होगा, इस समयावधि के पश्चात् पंजीयन का नवीनीकरण पुनः शुल्क सहित किया जायेगा।

01 अक्टूबर 2007

प्रदेश में रबी सीजन में बिजली आपूर्ति की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। ऊर्जा मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार ने इस संबंध में हर संभाग में समीक्षा करने का निर्णय लिया है। ऊर्जा मंत्री ने विधायकों और अधिकारियों के साथ आपूर्ति को लेकर हर पहलू पर विस्तृत विचार-विमर्श किया और व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के रास्ते सुझाए। समीक्षा बैठकों में विद्युत प्रदाय की समयावधि, वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थिति, विधायकों की क्षेत्रीय मांग और शिकायतें, निम्न दाब लाइनों के रख-रखाव, बकाया राशि की वसूली, अनधिकृत विद्युत उपयोग की रोकथाम और सुविधा योजना तथा अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति आदि बिन्दुओं पर चर्चा होगी।

04 अक्टूबर 2007

मध्यप्रदेश सरकार ने पन्ना जिले की पवई वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के केडेस्ट्रल और टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण कार्य की चार करोड़ 98 लाख 49 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके अंतर्गत केडेस्ट्रल और टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण कार्य की लागत एक करोड़ 72 लाख 57 हजार रुपये है। इसके अलावा पन्ना जिले की लिपरी तालाब योजना के बायीं तट पर मिट्टी का कार्य पड़ल खुदाई भराई बोल्डर को दो फिल्टर एवं चिपिंग के कार्य के लिये 11 करोड़ 41 लाख 15 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत दो करोड़ 8 लाख 13 हजार रुपये के कार्यों के लिये भी निविदा स्वीकृत की गई है।

06 अक्टूबर 2007

मध्यप्रदेश शासन ने मध्यप्रदेश वेट अधिनियम 2002 की धारा-4 तथा वेट नियम के नियम चार में निहित प्रावधान के अनुसार मध्यप्रदेश अपील बोर्ड में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिये चयन समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष मुख्य सचिव बनाए गए हैं। सदस्यों के रूप में प्रमुख सचिव विधि, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन एवं प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर विभाग शामिल रहेंगे।

07 अक्टूबर 2007

मध्यप्रदेश शासन ने राज्य में नई दवा नीति के अंतर्गत दवा एवं अन्य सहयोगी उपकरण आदि सामग्री क्रय करने के लिये केन्द्रीकृत क्रय व्यवस्था लागू की है। अब कोई भी संचालक/विभागाध्यक्ष अपने स्तर से (दवा नीति में दर्शायी गई सीमा एवं सामग्री को छोड़कर) सीधे क्रय आदेश जारी करने एवं उपार्जन की कार्यवाही नहीं करेंगे। समस्त उपार्जन स्वास्थ्य संचालनालय में गठित दवा प्रकोष्ठ के माध्यम से किया जायेगा। शासन द्वारा दवा प्रकोष्ठ को यह हिदायत दी गई है कि उपार्जन आदेश जो दवा प्रकोष्ठ से जारी होता है की प्रतिलिपि, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त को भी अंकित की जाये।

09 अक्टूबर 2007

मध्यप्रदेश शासन ने राज्य के चार जिलों को प्राकृतिक आपदा में प्रभावितों को राहत संबंधी कार्यों के लिये 32 लाख 41 हजार एक सौ 27 रुपये की राशि आवंटित की गयी है। पिछले साल अगस्त में आई बाढ़ से बचाव एवं राहत कार्यों के लिये बुलाये गए हेलीकॉप्टर के देयक के भुगतान के लिये भोपाल कलेक्टर को 24 लाख 57 हजार रुपये आवंटित किये गये हैं। इस वर्ष जुलाई में राजगढ़ जिले में आई बाढ़ से प्रभावितों को वितरित खाद्यान्न एवं केरोसीन के उचित मूल्य की दुकानों के लंबित देयकों के भुगतान के लिये राजगढ़ कलेक्टर को 6 लाख 17 हजार 2 सौ 50 रुपये आवंटित किये गये हैं। ओलावृष्टि में सहायता राशि प्रकरणों के अभिलेख तैयार करने में हुए व्यय के लंबित देयकों के भुगतान के लिये एक

लाख 27 हजार 5 सौ 98 रुपये की राशि आवंटित की गयी है। भिण्ड जिले के कुछ गांवों में बाढ़ प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के कार्यों में व्यय के लंबित देयकों के भुगतान के लिये भिण्ड, कलेक्टर को 39 हजार 2 सौ 79 रुपये लंबित किये गये हैं।

10 अक्टूबर 2007

मध्यप्रदेश के 10 जिलों में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा पिछले सितम्बर माह के दौरान 8,843 एकबत्ती कनेक्शन दिए गए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के छह महीनों में ऐसे उपभोक्ताओं को कुल 12 हजार 774 एकबत्ती कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इस अंतराल में अब तक चार गांवों में विद्युतीकरण के लिये लाइनों का विस्तार किया जा चुका है। इसके अलावा 716 कृषि पंपों को ऊर्जीकृत किया गया और 13 अनुसूचित जाति बहुल बस्तियों में विद्युतीकरण किया गया। इसके साथ ही 230 मजरों-टोलों का भी विद्युतीकरण किया गया।

11 अक्टूबर 2007

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न विभागों में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार संबंधी लंबित प्रकरणों की अभियोजन की स्वीकृति 15 दिनों के अंदर अधिकारियों को जारी करने के निर्देश दिये हैं। भोपाल में लोकायुक्त और राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुये श्री चौहान ने यह निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनियमितताओं और भ्रष्टाचार संबंधी प्रकरणों में विभागों में लंबित प्रकरणों को समय सीमा में निपटाया जाये, जिससे भ्रष्टाचार पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाया जा सके।

12 अक्टूबर 2007

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को लिखे एक पत्र में सहकारी बैंक को आयकर से छूट देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यह इसलिये आवश्यक है कि सहकारी बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित सरकार की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं साथ ही साढ़े चार हजार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं को वित्तीय मदद भी दे रही हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखे अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत सरकार के वार्षिक बजट 2006-07 में आयकर अधिनियम की धारा-80-पी के अंतर्गत सहकारी बैंकों को छूट संबंधी प्रावधान समाप्त कर दिये गये हैं। इसके फलस्वरूप प्रदेश की 4530 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के वित्तपोषण करने वाली 38 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों तथा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक संशोधित आयकर अधिनियम के दायरे में आ गयी हैं। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व में भारत सरकार ने समुपयुक्त नीति के अनुसार राज्य सहकारी बैंक तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को इस धारा से छूट प्रदान की थी।

13 अक्टूबर 2007

मध्यप्रदेश सरकार ने आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित राज्य के लगभग उन्नीस उच्चतर महाविद्यालयों में अतिरिक्त संकाय खोलने की मंजूरी दी है। सिवनी जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भिलाई तथा लखनादौन कन्या, खंडवा जिले के खार, अनूपपुर जिले के चचाई और खरगौन जिले के कन्या क्रमांक-1, धार जिले के सागौर, होशंगाबाद जिले के पथरोटा, बड़वानी जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धनोरा तथा ठीकरी कन्या विद्यालय में वाणिज्य संकाय

खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। इसी प्रकार सिवनी जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भीकमगढ़, धार जिले के कन्या कैसूर तथा मंडला जिले के निवास बालक विद्यालय में विज्ञान संकाय तथा खरगौन जिले के बमनाल तथा खंडवा जिले के आशापुर में कृषि संकाय, खंडवा जिले के खेड़ी में वाणिज्य तथा कृषि संकाय, बड़वानी जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्यापाटी तथा मंडवारा में गृह विज्ञान संकाय खोलने की मंजूरी दी है।

14 अक्टूबर 2007

मध्यप्रदेश के क्षेत्रीय वन मंडलाधिकारियों को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग में वन भूमि के व्यपवर्तन के संबंध में दिए गए अधिकारों की अवधि में वृद्धि की गई है। यह समय सीमा वृद्धि स्कूल अस्पताल भवन, विद्युत एवं संचार लाइन, पेयजल व्यवस्था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना, छोटी सिंचाई नहरें, गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत, कुशलता उन्नयन, विद्युत सबस्टेशन, संचार पोस्ट पुलिस स्टेशन, वॉच टॉवर कार्यों के लिये की गई है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने जनवरी 2005 में राज्य शासन को दो वर्षों के लिये एक हैक्टेयर से कम वन भूमि के कुछ जनोपयोगी गैरवानिकी कार्यों के लिये स्वीकृति के अधिकार प्रत्यायोजित किये थे।

17 अक्टूबर 2007

मध्यप्रदेश सरकार अगले महीने से राज्य के खेतिहर, भूमिहीन मजदूरों के कल्याण के लिये एक वृहद योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के माध्यम से खेतिहर मजदूर और उनके आश्रित परिवारजनों को बीमारी सहायता, रोजगार और बच्चों की पढ़ाई आदि को ध्यान में रखकर अनेक तरह के मदद के कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। योजना का लाभ लेने के लिये खेतिहर मजदूरों को अपना पंजीयन कराना होगा। किसान कल्याण एवं कृषि विकास तथा सहकारिता मंत्री गोपाल भार्गव ने सागर में यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार किसानों और गरीबों के उत्थान के लिये कृतसंकल्पित है। श्री भार्गव ने कहा कि सभी शासकीय अधिकारियों को किसानों और गरीबों के काम प्राथमिकता से करने के लिये निर्देशित किया गया है।

18 अक्टूबर 2007

मध्यप्रदेश शासन ने आदिवासी पोस्टमैट्रिक छात्रावासों में अंग्रेजी एवं अन्य विषयों की कोचिंग व्यवस्था एवं भुगतान के लिये 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2007-12 के लिये तीन करोड़ 28 लाख 20 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही वर्ष 2007-08 के लिये 63 लाख 20 हजार रुपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की है।

25 अक्टूबर 2007

मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अब तक 15 हजार 426 किलोमीटर लम्बी तीन हजार 360 सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। सड़कों के निर्माण पर कुल तीन हजार 487 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई है। उपरोक्त जानकारी देते हुए राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रुस्तम सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन एवं गुणवत्ता में देश में राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि गांवों तक सड़क साधन सुलभ होने से ग्रामीण इलाकों में शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में आशातीत सुधार परिलक्षित हो रहा है।

30 अक्टूबर 2007

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में मराठी अकादमी की स्थापना करने के संबंध में विचार कर निर्णय लिया जायेगा। श्री चौहान भोपाल में मराठी भाषी समन्वय परिषद् द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश के विकास में मराठी समाज के सहयोग का आव्हान करते हुये कहा कि सभी के सहयोग से प्रदेश को विकसित करने का उनका सपना साकार होगा। आने वाले वर्षों में मध्यप्रदेश बीमारू और पिछड़े राज्य की छवि से ऊपर उठकर विकसित राज्यों की पंक्ति में खड़ा होगा। मराठी भाषी समन्वय परिषद् के अध्यक्ष संजय पांडे ने प्रदेश में मराठी अकादमी के गठन एवं मराठी स्कूलों की संख्या बढ़ाने का आग्रह किया।

31 अक्टूबर 2007

मध्यप्रदेश शासन ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आँगनवाड़ियों में कार्यरत कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रोत्साहन राशि के भुगतान के आदेश जारी कर दिये हैं। इस आदेश के अनुसार आँगनवाड़ी कार्यकर्ता को 300 रुपये प्रतिमाह एवं सहायिकाओं को 150 रुपये प्रतिमाह की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। प्रमुख सचिव प्रशान्त मेहता ने महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल में यह जानकारी देते हुये बताया कि अक्टूबर की प्रोत्साहन राशि नवंबर के मानदेय के साथ दी जायेगी। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा जुलाई 2007 में आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मानदेय के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया था। शासन के इस निर्णय से करीब 69 हजार आँगनवाड़ी कार्यकर्ता और इतनी ही सहायिकाएं लाभान्वित होंगी।

02 नवम्बर 2007

मध्यप्रदेश शासन ने अनुसूचित जनजाति के कक्षा एक से आठ तक अध्ययनरत बालिकाओं एवं कक्षा एक से 12वीं तक अध्ययनरत पी.टी.जी. बालक-बालिकाओं को गणवेश प्रदाय करने के लिये 53 करोड़ 13 लाख रुपये की राशि मंजूर की है। यह राशि 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2007-12 के लिये स्वीकृत की गई है। इस राशि से आदिवासी विकास के लिये संचालित शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत बालक-बालिकाओं को गणवेश, स्वेटर, जूते, मोजे आदि सामग्री प्रदान की जायेगी। शासन ने वर्ष 2007-08 के लिये 8 करोड़ 68 लाख रुपये राशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की है।

04 नवम्बर 2007

मध्यप्रदेश शासन ने राज्य के नरसिंहपुर, गुना, रायसेन और बड़वानी जिलों के योजना मद से 118.92 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिये 44 करोड़ 51 लाख 37 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। नरसिंहपुर जिले में 13.20 किलोमीटर लंबी गाडरवारा, महगांवकला, आड़ेगांव सड़क निर्माण के लिये 5 करोड़ 24 लाख 83 हजार रुपये, गुना जिले में 9.92 किलोमीटर लंबी गुना नगरीय क्षेत्र की 11 सड़कों के उन्नतिकरण के लिये 4 करोड़ 84 लाख 33 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार, रायसेन जिले में 22.60 किलोमीटर लंबी गोरखपुर शालार्बरू प्रतापगढ़ सड़क निर्माण के लिये 6 करोड़ 87 लाख 50 हजार रुपये और 26.80 किलोमीटर लम्बी प्रतापगढ़ सियरमऊ सड़क की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही बड़वानी जिले में 46.40 किलोमीटर लंबी ठीकरी, बड़वानी, बावनगजा सड़क के डामरीकरण के लिये 20 करोड़ 62 लाख 70 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है

05 नवम्बर 2007

मध्यप्रदेश में इस महीने 15 नवम्बर को फाइलेरिया (हाथी पांव) रोकथाम दिवस मनाया जायेगा। राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अजय विश्नोई ने पंच-सरपंचों को पत्र लिखकर इस दिन अपने गांव और क्षेत्र में ग्रामीणों को दवा खिलवाने का आग्रह किया है। श्री विश्नोई ने पत्र में बताया कि फाइलेरिया की बीमारी प्रदेश के ग्यारह जिलों छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, सतना, रीवा, छिंदवाड़ा, कटनी, दतिया, सागर एवं उमरिया में आम है, जहां 15 नवंबर को फाइलेरिया दिवस का आयोजन होगा। इन ग्यारह जिलों में इस मौके पर लोगों को डी.ई.सी. गोली का सेवन कराया जायेगा। दो से पांच साल के बच्चों को एक गोली तथा 6 से 14 वर्ष के दो बच्चों को दो गोली एवं 15 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों को 3 गोली खिलाई जायेंगी। उल्लेखनीय है कि फाइलेरिया एक परजीवी, कृमि वाउकेरिया बेनक्रॉफ्टाई के कारण होता है, जो मनुष्य की लिम्फ ग्रंथि में रहता है।

06 नवम्बर 2007

मध्यप्रदेश शासन द्वारा टीकमगढ़ और छतरपुर जिले की 13 तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है। राज्य शासन द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर टीकमगढ़ जिले की टीकमगढ़, बल्देवगढ़, जतारा, पलेरा, निवाड़ी और पृथ्वीपुर तथा छतरपुर जिले की छतरपुर, राजनगर, नौगांव, लौंड़ी, गौरीहार, बिजावर और बड़ामलहरा तहसीलों को सूखा प्रभावित माना गया है।

07 नवम्बर 2007

मध्यप्रदेश में वन्य प्राणियों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध है तथा राज्य शासन ने इनके शिकार के लिये परमिट न देने का निर्णय लिया है। प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने यह जानकारी देते हुये बताया कि राज्य में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 लागू है जिसके अंतर्गत वन्यप्राणियों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध है। वन मंत्री ने कुछ समाचार पत्रों में प्रदेश में फसल नुकसान करने वाले वन्य प्राणियों का शिकार करने के लिये परमिट दिये जाने संबंधी प्रकाशित खबरों का खंडन किया। उल्लेखनीय है कि फसल नुकसान को रोकने के लिये नीलगाय को मारने के लिये वर्ष 2000 में एवं जंगली सुअर को मारने के लिये वर्ष 2003 में राज्य शासन द्वारा अनुमति दी गई थी। इस अनुमति के तहत किसान केवल अपने खेत पर ऐसे वन्य प्राणी को मारने के लिये अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व से आवेदन देकर अनुमति ले सकते हैं।

08 नवम्बर 2007

मध्यप्रदेश शासन ने टीकमगढ़ जिले के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की मजदूरी के भुगतान के लिये चालू वित्तीय वर्ष के बजट से जिला कलेक्टर को 2 करोड़ 76 लाख रुपये की राशि आवंटित की है। राज्य शासन द्वारा कलेक्टर को राहत कार्यों के संचालन के संबंध में स्थायी निर्देशों और मानदंडों के अनुसार उक्त राशि व्यय करने के निर्देश दिये गये हैं।

12 नवम्बर 2007

मध्यप्रदेश शासन ने संयुक्त संसदीय समिति को लाभ के पदों के संबंध में जानकारी देने के लिये एक चार सदस्यीय मंत्रिपरिषद् उपसमिति का गठन किया है। उप समिति में राज्य के गृह एवं परिवहन मंत्री, श्री हिम्मत कोठारी, वाणिज्य, उद्योग, रोजगार तथा आवास और पर्यावरण मंत्री श्री जयंत मलैया, जेल एवं विधि विधायी मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य और जल संसाधन एवं जनशिकायत निवारण मंत्री, श्री अनूप मिश्रा को सदस्य मनोनीत किया गया है। प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य मंत्रिपरिषद् उपसमिति के संयोजक होंगे।

13 नवम्बर 2007

मध्यप्रदेश शासन ने राज्य के टीकमगढ़ एवं छतरपुर जिले में सूखा राहत, रोजगार और पेयजल परिवहन के लिये कुल पांच करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। राहत आयुक्त द्वारा इस वर्ष के बजट से प्राकृतिक आपदा से संबंधित मद से दोनों जिलों को ढाई-ढाई करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। प्रत्येक जिले को सूखा राहत एवं रोजगार के लिये दो करोड़ रुपये और पेयजल व्यवस्था के लिये 50 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं। पेयजल व्यवस्था के लिये आवंटित राशि का उपयोग इन दोनों जिलों के सूखा प्रभावित ऐसे ग्रामों में पेयजल परिवहन के लिये किया जायेगा जहां पेयजल के अन्य समस्त स्रोत समाप्त हो गये हैं। प्रभावित गांवों में पेयजल परिवहन का कार्य ठेकेदारों से न करा कर ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की केंद्र ने सराहना की है। केंद्र का मानना है कि यदि अन्य राज्य मध्यप्रदेश की स्वास्थ्य योजनाओं को मॉडल के रूप में अपनायें तो उन्हें भी फायदा हो सकता है। नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद् के नौवें सम्मेलन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अंबुमणि रामदास ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से पता चलता है कि राज्य सरकार इस दिशा में कितना काम कर रही है। श्री रामदास ने कहा कि पिछले दो सालों के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान कार्यक्रमों की समीक्षा करने पर इस बात का संकेत मिलता है कि अब हमारी स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली बीमारी केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर मरीज केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित हो गई है।

14 नवम्बर 2007

मध्यप्रदेश शासन ने क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जलवायु परिवर्तन से संबंधित सी.डी.एम. कार्बन ट्रेडिंग व जलवायु परिवर्तन अनुकूल (क्लाईमेट चेंज एडॉप्टेशन) इत्यादि विषयों पर अंतर्विभागीय समन्वय के उद्देश्य से इन्वायरमेंट रिसोर्स सेल मॉनीटरिंग समिति का गठन किया है। राज्य योजना मंडल के उपाध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष और कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) इस समिति के सदस्य सचिव हैं। ग्रामीण विकास विभाग, वन, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, आवास एवं पर्यावरण, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा ऊर्जा विभाग के सचिव, प्रमुख सचिव और राज्य योजना मंडल के सदस्य सचिव इस समिति में सदस्य हैं। यह समिति प्रदेश में सी.डी.एम. एवं कार्बन ट्रेडिंग के लिये विभागीय गतिविधियों को चिन्हांकित करेगी। इसके अलावा राज्य की विभागीय गतिविधियों में सी.डी.एम. एवं कार्बन ट्रेडिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

15 नवम्बर 2007

मध्यप्रदेश शासन ने राज्य के सभी 48 जिलों को नवम्बर माह के लिये बी.पी.एल. को दिये जाने वाले खाद्यान्न के तहत 89 हजार 18 मैट्रिक टन खाद्यान्न का आवंटन किया है। आवंटित इस मात्रा में 61 हजार 6 मैट्रिक टन गेहूं और 28 हजार 12 मैट्रिक टन चावल शामिल हैं। खाद्य आयुक्त ने जिला कलेक्टरों को भेजे पत्र में स्पष्ट किया है कि केंद्र शासन द्वारा राज्य के बी.पी.एल. आवंटन में वृद्धि की जा सकेगी। जिलों को आवंटित खाद्यान्न का उठाव कर मांग अनुसार उचित मूल्य की दुकानों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिये गये हैं।

16 नवम्बर 2007

मध्यप्रदेश शासन ने कृषि विकास योजना के अंतर्गत परियोजना प्रस्तावों की स्वीकृति के लिये राज्य स्तरीय मंजूरी समिति का गठन किया है। मुख्य सचिव इस समिति के अध्यक्ष और कृषि उत्पादन आयुक्त उपाध्यक्ष हैं। प्रमुख सचिव/सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास इस समिति के सदस्य सचिव हैं। इस समिति के अन्य सदस्यों में कुलपति अथवा संचालक अनुसंधान सेवायें, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, प्रमुख सचिव वन, सचिव वित्त, सचिव जल संसाधन, संचालक कृषि, संचालक उद्यानिकी, संचालक पशु चिकित्सा सेवायें तथा संचालक मत्स्य पालन और योजना आयोग के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है।

19 नवम्बर 2007

मध्यप्रदेश शासन ने राज्य के ग्वालियर और भिण्ड जिले की आठ तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। राजस्व विभाग द्वारा इस आशय की सूचना जारी की गई है। जिन तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है उनमें ग्वालियर जिले की तीन तहसीलें ग्वालियर, डबरा और भितरवार तथा भिण्ड जिले की पांच तहसीलें भिण्ड, अटेर, लहार, मेहगांव और गोहद तहसील शामिल हैं।

20 नवम्बर 2007

मध्यप्रदेश सरकार भोपाल गैस त्रासदी में प्रभावित हुए गंभीर रोगियों और उनकी संतानों में बीमारियों के संबंध में शोध कार्यों को आगे बढ़ाएगी, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री श्री अजय विश्नोई ने यह जानकारी देते हुये बताया कि शोध कार्यों में इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि गंभीर बीमारी से प्रभावित गैस पीड़ित की किन-किन बीमारियों के लक्षण उसकी संतानों में मौजूद हैं। इसके लिये डी.एन.ए. जेनेटिक्स संबंधी शोध कार्य की योजना तैयार करने के निर्देश श्री विश्नोई ने अधिकारियों को दिये। श्री विश्नोई गैस राहत विभाग के पुनर्वास अध्ययन केंद्र की कार्यकारिणी समिति की बैठक में केंद्र द्वारा किए जा रहे शोध कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शोध कार्यों में उन वैज्ञानिकों को प्राथमिकता दी जायेगी, जो अभी इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं।

22 नवम्बर 2007

मध्यप्रदेश के बांधों और नहरों के आधुनिकीकरण के कार्यों की कुल 64 स्कीम माडर्नाइजेशन प्लान (एसएमपी) विश्व बैंक द्वारा अनुशंसित कर दी गई हैं। विश्व बैंक के सहयोग से राज्य में सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के लिये मध्यप्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट का संचालन किया जा रहा है। इसके क्रियान्वयन के लिये जल संसाधन विभाग के अधीन परियोजना क्रियान्वयन एवं समन्वय इकाई (पाइकू) का गठन किया गया है। इस परियोजना से प्रदेश के पांच नदी कछारों के अंतर्गत आने वाले 30 जिलों के 654 पुराने बांधों और उनकी नहरों का आधुनिकीकरण किया जायेगा। कुल 1919 करोड़ रुपये लागत की इस परियोजना की अवधि छह वर्ष है जो 2011 में पूर्ण होगी।

26 नवम्बर 2007

मध्यप्रदेश शासन ने एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि वन क्षेत्र में पाये जाने वाले जेट्रोफा बीज के परिवहन के लिये अभिवहन पास (टी.पी.) की आवश्यकता नहीं होगी। मध्यप्रदेश अभिवहन (वन उपज) नियम-2000 के अंतर्गत शासन द्वारा इस संबंध में वन विभाग के समस्त अधिकारियों को सूचित किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन की जारी अधिसूचना 24 जून, 2003 के द्वारा तेंदूपत्ता, साल बीज, कुल्लू गोंद को छोड़कर समस्त अविनिर्दिष्ट लघु वनोपज को

अभिवहन पास (टी.पी.) की आवश्यकता से मुक्त रखा गया है। चूंकि जेट्रोफा बीज विनिर्दिष्ट लघु वनोपज नहीं है अतः इसके परिवहन के लिये टी.पी. की जरूरत नहीं है।

29 नवम्बर 2007

मध्यप्रदेश के 867 वनग्रामों में अधोसंरचना विकास के लिये 260 करोड़ रुपये की विशेष योजना क्रियान्वित की जा रही है। भारत द्वारा स्वीकृत इस योजना को वन विभाग अभिकरणों के माध्यम से चलाया जा रहा है। योजना के अंतर्गत अब तक 867 वनग्रामों में 194 करोड़, 92 लाख रुपये राशि के विभिन्न कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। 260 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के अंतर्गत जल संसाधनों का विकास जैसे तालाब, ट्यूबवेल, हैण्डपंप, कुआं, स्टॉपडेम, सामुदायिक भवन, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क, रपटा, पुलिया निर्माण एवं वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

30 नवम्बर 2007

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल की बैठक में ग्वालियर शहर में पानी की आपूर्ति करने के लिये आमंत्रित निविदा प्रकरण में निविदाकारों की तकनीकी अर्हता को स्वीकृति प्रदान कर इसके अंतर्गत ककेटो और पेसरी जलाशयों के डेड स्टोरेज को लिफ्ट करके तिघरा जलाशय में डालने के लिये छह करोड़ 84 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई। श्री चौहान ने इस कार्य को शीघ्र पूरा किये जाने के निर्देश दिये। इसके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा तवा बांध की नहरों की लाइनिंग के लिये आवश्यकतानुसार 60 करोड़ रुपये स्वीकृत करने के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिये गये।

01 दिसम्बर 2007

मध्यप्रदेश में तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन राशि के वितरण का कार्य जारी है। इसके अंतर्गत अब तक लगभग 11 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि संग्राहकों को त्वरित वितरित की जा चुकी है। प्रदेश के 15 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को लगभग 41 करोड़ रुपये की राशि प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वितरित की जा रही है। वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने भोपाल में यह जानकारी देते हुये बताया कि शेष राशि के वितरण का कार्य भी युद्ध स्तर पर पूरे राज्य में प्रगति पर है। वर्ष 2005 के लिये 13.23 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पारिश्रमिक बंटना है वहीं वर्ष 2006 के लिये यह राशि लगभग दोगुनी 27.41 करोड़ रुपये वितरित की जा रही है। वन मंत्री ने बताया कि प्रदेश की वर्तमान सरकार ने वर्ष 2004 से प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में बांटी जाने वाली राशि का प्रतिशत शुद्ध आय के 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया गया है।

03 दिसम्बर 2007

मध्यप्रदेश सरकार ने भारत शासन से मांग की है कि राज्य के 59 लाख 75 हजार राशन कार्डों की संख्या के हिसाब से राज्य सरकार को 35 किलो प्रति परिवार के मान से आवंटन दिया जाये। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री अखंड प्रताप सिंह ने भोपाल में यह जानकारी देते हुये बताया कि राज्य में कुल 43 लाख 94 हजार 394 राशन कार्ड बी.पी.एल. के और 15 लाख 81 हजार 565 कार्ड अन्त्योदय योजना के हैं। अन्त्योदय योजना के हितग्राही परिवारों को 35 किलो प्रति कार्ड के मान से खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। शेष खाद्यान्न बी.पी.एल. राशन कार्डधारियों को लगभग 20 किलो 250 ग्राम प्रति कार्ड के औसत से वितरित किया जा रहा है।

04 दिसम्बर 2007

समाधान ऑन लाइन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद के हरीशंकर मालवीय को बेटी के विवाह के लिये 10 हजार रुपये का चेक प्रदान किया। श्री मालवीय ने कर्मकार सन्निर्माण मंडल द्वारा सहायता का आवेदन प्रस्तुत किया था। उल्लेखनीय है कि हर माह एक बार समाधान ऑन लाइन कार्यक्रम होता है जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता से रूबरू हो उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निवारण करते हैं।

05 दिसम्बर 2007

मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के तामिया तहसील स्थित प्रसिद्ध पातालकोट में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा गंतव्य विकास योजना के अंतर्गत पातालकोट के विकास के लिये 3 करोड़ 25 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत ट्रेकिंग रूट, व्यू पाइंट, पार्किंग एरिया आदि निर्माण कार्य शुरू किये गये हैं। पातालकोट को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और पर्यटकों के रुकने के लिये कैंपिंग साइट का संचालन वन विभाग करेगा। इसके लिये वन विभाग ने संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत गठित वन समितियों एवं स्व-सहायता समूह को पातालकोट के रातेड़ गांव में निर्मित हो रहे कैंपिंग साइट का संचालन एवं निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है।

14 दिसम्बर 2007

मध्यप्रदेश शासन ने प्रदेश के तीन सूखा प्रभावित जिलों टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना के नगरीय क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था करने के लिये कुल 60 लाख रुपये की राशि प्रदान की है। राहत आयुक्त द्वारा संबंधित जिला कलेक्टर्स को उक्त राशि आवंटित की गई। प्रत्येक जिले को 20 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं।

15 दिसम्बर 2007

मध्यप्रदेश शासन ने उच्च न्यायालय के प्रस्ताव अनुसार वित्तीय वर्ष 2007-08 में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 के लिये राज्य के विभिन्न जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर 108 कोर्टरूम निर्मित करने की स्वीकृति प्रदान की है। शासन ने प्रति कोर्टरूम की लागत 13 लाख 82 हजार रुपये की दर से 108 कोर्टरूम के लिये 14 करोड़ 92 लाख 56 हजार रुपये की प्रशासकीय एवं नौ लाख 25 हजार 925 रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। राज्य शासन ने संबंधित कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, भवन तथा पथ को निर्देश दिये हैं कि आदेश जारी होने के दिनांक से सात दिवस की अवधि के अंदर कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें तथा वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व कार्य पूर्ण किया जाये।

15 दिसम्बर 2007

मध्यप्रदेश शासन ने उच्च न्यायालय के प्रस्ताव अनुसार वित्तीय वर्ष 2007-08 में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 के लिये राज्य के विभिन्न जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर 108 कोर्टरूम निर्मित करने की स्वीकृति प्रदान की है। शासन ने प्रति कोर्टरूम की लागत 13 लाख 82 हजार रुपये की दर से 108 कोर्टरूम के लिये 14 करोड़ 92 लाख 56 हजार रुपये की प्रशासकीय एवं नौ लाख 25 हजार 925 रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। राज्य शासन ने संबंधित कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, भवन तथा पथ को निर्देश दिये हैं कि आदेश जारी होने के दिनांक से सात दिवस की अवधि के अंदर कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें तथा वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व कार्य पूर्ण किया जाये।

18 दिसम्बर 2007

वनमंत्री कुंवर शाह ने वन विभाग के कर्मचारी प्रतिनिधियों को आश्वस्त करते हुये कहा कि राज्य शासन वन विभाग की नवीन संरचना में सभी संवर्ग में पदों को बढ़ाने पर विचार करेगा। विभाग के संयुक्त कर्मचारी मोर्चा संघ के प्रतिनिधियों के साथ उनकी लंबित मांगों पर चर्चा के दौरान श्री शाह ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रत्येक संवर्ग में पूर्ण सेवाकाल में अनिवार्य रूप से पदोन्नति पर भी ध्यान दिया जायेगा। इसके अलावा वन विभाग के कार्यपालिक एवं लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को शासन के अन्य विभागों में प्रचलित मकान भाड़ा एवं अन्य सुविधा देने का भी पूर्ण प्रयास किया जायेगा।

19 दिसम्बर 2007

एड्स से बचाव के लिये सभी को एकजुट होकर प्रयास करना होगा, तभी एड्स के प्रसार को कम किया जा सकेगा। यह बात मध्यप्रदेश एड्स कंट्रोल समिति की परियोजना संचालक श्रीमती सलीना सिंह ने रेड रिबन एक्सप्रेस के इटारसी रेलवे स्टेशन पहुंचने के अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि इटारसी प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, यहां देश भर से लोगों की आवाजाही रहती है, जिसको देखते हुये एच.आई.वी./एड्स की जाँच सुविधा आमजनों को उपलब्ध कराने, शीघ्र ही जनसेवा स्वास्थ्य केंद्र में एकीकृत जांच एवं परामर्श केंद्र स्थापित किया जायेगा।

16 दिसम्बर 2007

शिक्षा को सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लक्ष्य के अंतर्गत कम्प्यूटर कम्पनी माइक्रोसॉफ्ट विश्वभर में 'शैक्षिक कार्यक्रम में सहभागी' अभियान संचालित कर रही है। मध्यप्रदेश में भी राज्य शिक्षा केंद्र के साथ 'प्रोजेक्ट शिक्षा' नामक अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राज्य के आठ जिलों में शिक्षा विभाग के अध्यापकों एवं अधिकारियों को सूचना प्रौद्योगिकी का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर का उपयोग करने वाले शिक्षकों के प्रोत्साहन के लिये 'नवाचारी शिक्षक नेतृत्व अवार्ड' की स्थापना की है। इस अवार्ड के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों से शिक्षकों का चयन कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जायेगा।

17 दिसम्बर 2007

राज्य सरकार के नई दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन को दिल्ली सरकार ने ऊर्जा बचत के लिये पुरस्कृत किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री सुश्री शीला दीक्षित ने ऊर्जा उपयोग में पिछले वर्ष उल्लेखनीय योगदान के लिये दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में मध्यप्रदेश भवन की ओर से उप आवासीय आयुक्त एल.के.एस. चौहान को नवीनीकरण ऊर्जा राज्य पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार कुल आठ संस्थानों को ऊर्जा कुशल एवं नवीकरण ऊर्जा के बचत उपकरणों के इस्तेमाल के लिये प्रदान किया गया। पुरस्कृत आठ संस्थानों में से मध्यप्रदेश भवन एकमात्र ऐसा राज्य संस्थान है एवं केवल दो चयनित शासकीय संस्थानों में से एक है।

21 दिसम्बर 2007

प्रदेश के संस्कृति, जनसंपर्क एवं खनिज साधन मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा है कि संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश के दूरस्थ अंचलों में विशेषकर आदिवासी वर्ग की साहित्यिक प्रतिभाओं के विकास के लिये हरसंभव मदद देगा। साहित्य अकादमी की तरफ से जनजातीय वर्ग के रचनाकारों को उनकी प्रथम रचना के प्रकाशन के लिये अनुदान उपलब्ध कराया

जायेगा। श्री शर्मा साहित्य अकादमी मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद् द्वारा भोपाल के हिन्दी भवन में आयोजित अनुसूचित जनजातीय लेखकों की 'सृजन-संवाद' कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग की प्रतिभाओं को आगे आने के लिये छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। संस्कृति मंत्री ने इस अवसर पर राज्य के विभिन्न आदिवासी अंचलों की समृद्ध संस्कृति की प्रशंसा की।

देवेन्द्र जोशी

....